मासिक, फरवरी-2022

₹15/-

परफेक्ट न्यूज

बजा चुनावी बिगुल
नेताओं ने कसी कमर

RNI No.DELHIN/2012/47314

Delhi College of Fire Safety Engineering
Plot No 120 Dhul siras Sector 24, Dwarka New Delhi-110075
Phone :- 32085353,54 M 9811110534, 9311110534

AFFILIATED TO BOARD OF TECHNICAL EDUCATION, DELHI (GOVT.OF NCT OF DELHI)

PRESS RELEASE

I) Six Months Certificate Course in Fire Fighting

Eligibility 10th Passed

II) One Year Certificate Course in Fire Technology & Industrial Safety Management Eligibility 10 +2

III) Trade Diploma in Environment& Health Safety (10 Passed)

HOW TO APPLY

Prospectus and Application form can be Obtained on Payment of Rs300 in cash or via DD drawn in favour of the institute payable at Delhi application form can also be downloaded from website.

ADDRESS:

Delhi College of fire and safety Engineering

ADDRESS –Plot no 975Mundka New delhi-110041

परफेक्ट न्यूज़
वर्ष-10, अंक-2, फरवरी-2022

RNI No. DELHIN/2012/47314
Declaration No. (P-1) Press 2012

प्रधान संपादक
विवेकानन्द बाईजोडिया

संपादक
नलिन रंजन सिंह

उपसंपादक
अधिवक्ता कैलाश चंद

लखनऊ ब्योरो
सी.ए. चन्दन गुप्ता

पटना ब्योरो
अभिनव राज

विशेष संवाददाता
प्रहलाद सिन्हा

मार्केटिंग
वीरभद्र सेन

कानूनी सलाहकार
जीतेंद्र कुमार भिलौरिया

सब्सक्रिप्शन की जानकर एवं प्रसार की शिकायत के लिए ई-मेल करें
perfectnews07@gmail.com

सम्पादकीय कार्यालय
3 बी, दीप इन्कलेव एक्सटेंशन, पार्ट-2, विकास नगर, उत्तम नगर, दिल्ली-59
मोबाइल: 8010312843
मेल: perfectnews07@gmail.com

स्वामी मुद्रक प्रकाशक विवेकानन्द बाईजोडिया, संपादक नलिन रंजन सिंह द्वारा मंयक आफसेट प्रोसेस, 794/95, गुरु रामदास नगर, एक्सटेंशन लक्ष्मीनगर, दिल्ली-110092 से मुद्रित कराकर 3 बी, दीप इन्कलेव एक्सटेंशन, पार्ट-2, विकास नगर, उत्तम नगर, दिल्ली-59 से प्रकाशित।

सभी विवाद दिल्ली न्यायलय द्वारा निपटाए जाएंगे।

संपादकीय

दागी उम्मीदवार बनाम स्वच्छ चुनाव

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की शुचिता और स्वच्छता पर खतरा लगातार गहराता जा रहा है। बेशक, कभी सार्वजनिक जीवन में बेदाग लोगों की वकालत की जाती थी, लेकिन अब यह आम धारणा है कि राजनेता और अपराधी एक-दूसरे के पर्याय हो चले हैं। 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स" यानी एडीआर की रिपोर्ट भी इसकी तस्दीक करती है। एडीआर की ताजा अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक, 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश की जिन 58 विधानसभा सीटों पर मत डाले जाएंगे, वहां से कुल 623 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें से 615 उम्मीदवारों के बारे में एडीआर को सूचनाएं मिली हैं। इन 615 प्रत्याशियों में से 156, यानी करीब 25 फीसदी उम्मीदवार दागी हैं। 121 पर तो गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें दोषसिद्ध होने पर पांच साल या इससे भी अधिक की सजा वाले गैर-जमानती जुर्म शामिल हैं। जैसे, हत्या-अपहरण-बलात्कार आदि। विडंबना यह है कि हरेक सियासी पार्टी राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता जाहिर करती है और इसे रोकने के दावे करती है, लेकिन जब चुनाव में टिकट बांटने का वक्त आता है, तब दागी छवि वाले प्रत्याशियों पर भरोसा किया जाता है। यही वजह है कि चुनाव-दर-चुनाव ऐसे सांसदों-विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिन पर आपराधिक मामले चल रहे होते हैं। उत्तर प्रदेश में ही 2017 के विधानसभा चुनाव में जीतकर आए 402 विधायकों में से 143 (36 प्रतिशत) ने अपने चुनावी हलफनामे में खुद के ऊपर आपराधिक मामले चलने की बात कही, जबकि गंभीर आपराधिक मामलों का सामना करने वाले विधायकों की संख्या 107 थी, यानी विधानसभा सदस्यों का 26 प्रतिशत। 2012 की राज्य विधानसभा में ये आंकड़े क्रमशः 47 प्रतिशत (189 विधायक दागी छवि वाले) और 24 प्रतिशत (98 विधायक गंभीर मामलों में आरोपी) थे। यह महज एक राज्य का मसला नहीं है। एडीआर की ही रिपोर्ट बताती है कि संसद के निचले सदन में दागी छवि वाले सांसदों की मौजूदगी हर चुनाव में बढ़ रही है। मौजूदा लोकसभा के लिए 2019 में जीतने वाले 539 सांसदों में से 233, यानी 43 प्रतिशत सदस्यों ने खुद पर आपराधिक मामले होने की जानकारी दी है, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 542 विजेताओं में से 185 दागी चुनकर आए थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत (543 सांसदों में से 162) था। यानी, 2009 से 2019 तक आपराधिक छवि वाले सदस्यों की लोकसभा में मौजूदगी 44 फीसदी बढ़ गई थी। इसी तरह, गंभीर आपराधिक मामलों में मुकदमों का सामना करने वाले सांसदों की संख्या 2009 में 76, 2014 में 112 और 2019 में 159 थी, यानी 2009 से 2019 तक इसमें 109 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। चूंकि चुनाव-दर-चुनाव आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की जीत का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए राजनीतिक दल भी मानो अब यह मान चले हैं कि दागी छवि जीत की गारंटी है। वैसे भी, चुनावों में हर हाल में जीत हासिल करना ही राजनीतिक पार्टियों का मकसद होता है। इसके लिए वे हर वह तरीका अपनाने को तैयार रहते हैं, जिनसे उनकी मौजदूगी सदन में हो। कुछ जन-प्रतिनिधि यह तर्क देते हैं कि राजनीति से प्रेरित मुकदमे उनके ऊपर लादे गए हैं। यह कुछ हद तक सही भी है। मगर चुनाव आयोग और अदालत, दोनों का यह मानना रहा है कि जिन उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनको तो चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने तो इसके लिए तीन मापदंड बनाए हैं- मुकदमा अगर साल भर से ज्यादा पुराना हो, उम्मीदवार पर पांच साल या उससे अधिक वर्ष की सजा वाले अपराध के आरोप हों और तीसरा, निचली अदालत में चार्जशीट पेश कर दी गई हो और कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया हो। आयोग का मानना है कि इस तरह के उम्मीदवारों को चुनाव में टिकट नहीं मिलने चाहिए। मगर मुश्किल यह है कि राजनीतिक दल इन सिफारिशों को अपनाने को तैयार नहीं दिखते। दागी छवि वाले एक और तर्क गढ़ते हैं कि कानूनन जब तक दोष साबित न हो जाए, वे निर्दोष हैं। मैं इसका जवाब एक अन्य सवाल से देता हूं। प्रश्न यह है कि हिन्दुस्तान की जेलों में चार से सवा चार लाख कैदी बंद हैं, जिनमें से 2.71 लाख के करीब विचाराधीन हैं।

देश को शहंशाह की तरह चलाने की कोशिश हो रही है : राहुल गांधी

जिलेसिंह लाकड़ा, वरिष्ठ पत्रकार

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि देश को 'शहंशाह" की तरह चलाने की कोशिश हो रही है तथा इस सरकार की नीतियों के चलते आज देश आंतरिक एवं बाहरी मोर्चों पर 'बड़े खतरे" का सामना कर रहा है।

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने यह दावा भी किया कि केंद्र सरकार की नीति के कारण ही आज चीन एवं पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार में दो हिंदुस्तान बन गए हैं जिनमें से एक अमीरों और दूसरा गरीबों के लिए है। राहुल गांधी ने यह दावा भी किया कि देश के सामने खड़ी प्रमुख चुनौतियों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।

गांधी ने सत्तारूढ़ भाजपा पर 'हिंदुस्तान के राजा" होने के विचार जिसे '1947 में खत्म किया गया था 'को वापस लाने का आरोप लगाया और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 'एक राजा होने का विचार वापस आ गया है।"

उन्होंने कहा, 'भारत को संविधान में राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है न कि एक राष्ट्र के रूप में। भारत में एक राज्य के लोगों पर कोई शासन नहीं कर सकता है। विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को दबाया नहीं जा सकता। यह एक साझेदारी है, किसी एक का राज नहीं।"

सहयोगात्मक संघवाद के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत पर दशकों से शासन करने का एकमात्र तरीका बातचीत के माध्यम से रहा है।

उन्होंने कहा, 'कांग्रेस ने राजा होने वाले विचार को 1947 में ही खत्म कर दिया था, लेकिन अब ये वापस आ गया है। एक ऐसा नजरिया है कि देश को केवल केंद्र के डंडे से ही हांका जा सकता है, लेकिन जब-जब ऐसा हुआ है, ऐसे डंडे को तोड़ दिया गया है।"

लगभग चालीस मिनट चले भाषण में उन्होंने कहा, 'आप भारत में शासन करने वाले किसी साम्राज्य को देख लीजिए। आप अशोक महान को देख लें, मौर्य वंश को देख लें, आप यह पाएंगे कि आपसी संवाद के जरिये शासन किया गया।"उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार

विभिन्न राज्यों की आवाज दबा रही है, लेकिन उसे इसका आभास नहीं है कि देश के 'संस्थागत ढांचे" पर हमले की प्रतिक्रिया हो सकती है।

उन्होंने कहा, 'मेरे परनाना (जवाहरलाल नेहरू) इस राष्ट्र को बनाने के लिए ही 15 साल तक जेल में रहे, मेरी दादी (इंदिरा गांधी) को 32 गोलियां मारी गईं और मेरे पिता (राजीव गांधी) को विस्फोट से उड़ा दिया गया। इन्होंने इस राष्ट्र को बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। इसलिए मैं थोड़ा बहुत जानता हूं कि राष्ट्र क्या है।"

गांधी ने कहा, आप खतरे से खेल रहे हैं। मेरी सलाह है कि रुक जाइए। अगर आप नहीं रुके तो समस्या खड़ी कर देंगे। समस्या पहले ही शुरू हो चुकी है।"

गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार के पास इतिहास के बारे में कोई विचार नहीं है और वह एक शहंशाह के विचार के तले राज्यों के संघ की अवधारणा को दबाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने आगे कहा, 'इस देश के दो नजरिये हैं। एक नजरिया यह है कि देश राज्यों का संघ है जिसका मतलब है कि संवाद और बातचीत से निर्णय लिए जाएंगे- यानी बराबर की साझेदारी। दूसरा नजरिया देश को 'शहंशाह" की तरह चलाने का है। इसने तीन हजार साल में कभी काम नहीं किया। भाजपा के ऐसे गलत नजरिये ने हमारे देश को कमजोर किया है।"

उन्होंने कहा कि भारत कमजोर हो रहा है और पूरी तरह से अलग-थलग है। उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान किसी विदेशी गणमान्य के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद न होने को लेकर भी सवाल उठाया।

उन्होंने कहा, 'हम श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन से घिरे हुए हैं। हर जगह हम घिरे हुए हैं। हमारे विरोधी हमारी स्थिति को जानते हैं।"

सीमा पर चीन की आक्रामकता और पाकिस्तान की सीमा से जुड़ी चुनौती का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, 'आप खतरे को हल्के में मत लीजिए। आप चीन और पाकिस्तान को साथ ला चुके हैं, यह भारत के लोगों के साथ सबसे बड़ा अपराध है।"

उन्होंने कहा, 'मुझे कोई संदेह नहीं है कि चीन के पास स्पष्ट योजना है। इसकी बुनियाद डोकलाम और लद्दाख में रख दी गई है। यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपने जम्मू कश्मीर और विदेश नीति में बहुत बड़ी रणनीतिक गलतियां की हैं।।आपने दो मोर्चों को एक मोर्चे में बदल दिया है।"

राहुल गांधी ने दावा किया, 'मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि हमने बड़ी गलतियां की हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम चीन के खिलाफ अपनी रक्षा कर सकें। याद रखिये जो मैं कह रहा हूं। अगर कुछ होता है तो आप जिम्मेदार होंगे। आप हमें सुनिए। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्हें इन मुद्दों की गहरी समझ है।"

कांग्रेस नेता ने कहा, 'आज देश बड़े खतरे का सामना कर रहा है। यह खतरा आंतरिक भी है और बाहरी भी। मैं अपने प्रिय देश को इस स्थिति में नहीं देख सकता। यह देखकर मुझे दुख होता है।"

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश के संघीय ढांचे पर हमले का आरोप लगाया और दावा किया, 'भाजपा असमंजस में है। समस्या यह भी है कि भाजपा को लगता है कि देश की अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों, इतिहास को दरकिनार किया जा सकता है।"

कांग्रेस नेता ने बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नौकरी छूटने का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति का संबोधन रणनीतिक दृष्टि के बजाय नौकरशाही के विचारों की एक सूची थी, यह मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसे नेतृत्व की दृष्टि से नहीं बल्कि नौकरशाहों के एक समूह द्वारा बनाया गया था।"

कांग्रेस नेता ने कहा, 'अभिभाषण में कई रणनीतिक मुद्दों को नहीं छुआ गया है। कई प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख नहीं हुआ। तीन बुनियादी विषयों पर इसमें बात नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण है कि अब दो भारत हैं। एक अमीरों का हिंदुस्तान है, दूसरा हिंदुस्तान गरीबों के लिए है। इनमें खाई बढ़ती जा रही है।"

वायनाड सांसद ने कहा, 'आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हैं, मेड इन इंडिया अब संभव नहीं है। आपने 'मेड इन इंडिया" को नष्ट कर दिया है। आपको छोटे और मध्यम उद्योगों का साथ की आवश्यकता है, अन्यथा 'मेड इन इंडिया" संभव नहीं है। छोटे और मझोले उद्योग ही रोजगार पैदा कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा, 'अभिभाषण में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं है। आज देश का युवा रोजगार ढूंढ़ रहा है। यह सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है।"

राहुल गांधी ने आरोप लगाया, 'पिछले साल तीन करोड़ युवाओं को रोजगार गंवाने पड़े। बीते 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में आज है इस सरकार ने असंगठित क्षेत्र और छोटे कारोबारों पर आक्रमण किया। नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी लागू करके आक्रमण किया गया।"

उन्होंने दावा किया कि असंगठित क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया" लागू हो ही नहीं सकता है, इस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया गया है।

उन्होंने जोड़ा, 'आप मेड इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया आदि के बारे में बात करते रहते हैं और बेरोजगारी केवल बढ़ रही है। संप्रग सरकार ने 10 साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था लेकिन इस सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी में पहुंचा

गांधी ने सरकार पर न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पेगासस स्पायवेयर का इस्तेमाल 'राज्यों के संघ की आवाज को खत्म करने के औजार" के रूप में करने का भी आरोप लगाया।

राहुल ने यह भी कहा, 'प्रधानमंत्री को सुझाव देता हूं कि कि आप दो भारत बना रहे हैं। कृपया दोनों हिंदुस्तान को साथ लाने की दिशा में काम करें जिन्हें आपकी सरकार ने पैदा किया है।"कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि देश की संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में है। राहुल गांधी ने दो उद्योगपतियों का उल्लेख करते हुए कहा, 'कोरोना के समय कई वैरिएंट आते हैं, लेकिन 'डबल ए" वैरिएंट है जो देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि मणिपुर के एक राजनीतिक नेता ने उन्हें बताया कि उन्हें गृह मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान कथित तौर पर जूते उतारने के लिए कहे जाने पर अपमानित महसूस हुआ। राहुल गांधी ने यह दावा भी किया कि मणिपुर के कुछ लोगों ने उन्हें जानकारी दी कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान उनके जूते उतरवाए गए। उन्होंने कहा, 'मेरे पास इसकी तस्वीर हैं। मैं इसे दिखा सकता हूं।"

राहुल ने कहा, 'कुछ दिन पहले, एक राजनीतिक नेता, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मणिपुर से मेरे पास आए थे। वह बहुत आक्रोशित थे। मैंने कहा 'तुम नाराज क्यों हो मेरे भाई" तो उन्होंने कहा 'राहुल जी मैंने इससे पहले कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया जितना कुछ दिन पहले से कर रहा हूं"।"

राहुल ने कहा कि उक्त नेता ने उन्हें बताया कि मणिपुर के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मिलने गया था।

इसके बाद उन्होंने नेता को उद्धृत करते हुए कहा कि शाह के घर के बाहर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को अपने जूते उतारने के लिए कहा गया था और जब वे गृह मंत्री के कमरे के अंदर गए, तो उन्होंने पाया कि उन्होंने अपनी 'चप्पल" पहनी हुई थी। राहुल ने सवाल किया, 'इसका क्या मतलब है? इसका वास्तव में क्या मतलब है? ऐसा क्यों है कि गृह मंत्री के घर में वह 'चप्पल" पहन सकते हैं लेकिन मणिपुरी राजनेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ऐसा नहीं कर सकता?" सत्तापक्ष के सदस्यों ने जब इस दावे को चुनौती दी तो पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि उन्होंने भी आरोप की सत्यता पर सवाल उठाया था लेकिन मणिपुर के नेता ने उन्हें तस्वीरें दिखाईं। राहुल ने कहा कि यह भारत के सामने पेश आने का तरीका नहीं है।

दिया।""

उन्होंने कहा, 'मुझे बड़े उद्योगों से कोई दिक्कत नहीं है, उन पर ध्यान दीजिए, लेकिन इसका एहसास करिये कि ये बड़े उद्योग रोजगार पैदा नहीं कर सकते। छोटे और मझोले उद्योग ही युवाओं के लिए नौकरियां पैदा कर सकते हैं।"

कांग्रेस सांसद ने नौकरियों को लेकर बिहार में रेलवे के उम्मीदवारों के विरोध-प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार नौकरी देने में असमर्थ है।

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, 'ऐसा लगता है कि एक किंग हैं, शहंशाह हैं, शासकों के शासक हैं किसान एक साल तक बैठे रहे, लेकिन किंग उनकी बातों से सहमत नहीं हुए।"

पीएनबी के सर्वर में सेंध, सात माह तक उजागर होती रही 18 करोड़ ग्राहकों की जानकारी : रिपोर्ट

साइबर सुरक्षा कंपनी साइबरएक्स9 ने रविवार को दावा किया कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के सर्वर में कथित तौर पर सेंधमारी से करीब 18 करोड़ ग्राहकों की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी लगभग सात महीनों तक 'उजागर" होती रह।

साइबरएक्स9 ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में सुरक्षा खामी से यह साइबर हमला प्रशासनिक नियंत्रण के साथ उसकी संपूर्ण डिजिटल बैंकिंग प्रणाली तक हुआ है।

इस बीच, पीएनबी बैंक ने तकनीकी गड़बड़ी की पुष्टि करते हुए सर्वर में सेंध से ग्राहकों की महत्वपूर्ण जानकारी के खुलासे से इनकार किया है। बैंक ने कहा, 'इसके कारण ग्राहकों के ब्योरे/एप्लिकेशंस पर कोई असर नहीं पड़ा और सर्वर को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है।"

वही साइबरएक्स9 के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हिमांशु पाठक ने बताया, 'पंजाब नेशनल बैंक पिछले सात महीनों से अपने 18 करोड़ से अधिक ग्राहकों के कोष, व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी की सुरक्षा से गंभीर रूप से समझौता करता रहा। पीएनबी तब जागा और उसने इस 'सेंधमारी" को ठीक किया जब साइबरएक्स 9 ने इसका पता लगाया और सीईआरटी-इन और एनसीआईआईपीसी के माध्यम से बैंक को सूचित किया।"

उन्होंने कहा कि साइबरएक्स9 की शोध टीम ने पीएनबी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा चूक का पता लगाया जिसके कारण आंतरिक सर्वर तक प्रभावित हो रहा था।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पाठक ने कहा कि एक एक्सचेंज सर्वर में खामी पाई गई जो अन्य एक्सचेंजों के साथ जुड़ा हुआ है और सभी एक्सेस साझा करता है- जिसमें ईमेल पते तक एक्सेस भी शामिल होती है।"

उन्होंने कहा, 'जिस सेंधमारी का हमने पता लगाया, वह पीएनबी के एक्सचेंज सर्वरों में उच्चतम स्तर के व्यवस्थापकीय विशेषाधिकार की ओर ले जा रही थ। यदि आप एक्सचेंज सर्वर के माध्यम से डोमेन कंट्रोलर तक एक्सेस पा लेते हैं तो नेटवर्क में मौजूद किसी भी कंप्यूटर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इनमें वो सभी कंप्यूटर भी शामिल हैं जिनका उपयोग बैंक की शाखाओं और अन्य विभागों में किया जा रहा है।"

वहीं, पीएनबी से इस संबंध में पूछे जाने पर कहा कि जिस सर्वर में सेंधमारी की बात सामने आई है उसमें कोई संवेदनशील या महत्वपूर्ण जानकारी नहीं थ।

पीएनबी ने कहा, 'जिस सर्वर में सुरक्षा खामी की सूचना दी गई थी, उसका इस्तेमाल कई एक्सचेंज हाइब्रिड सर्वरों में से एक के रूप में किया जा रहा था, जिसका इस्तेमाल ऑन-प्राइम से ऑफिस 365 क्लाउड पर ईमेल को रूट करने के लिए किया जाता था। इस सर्वर में कोई संवेदनशील/महत्वपूर्ण डेटा नहीं है।"

पीएनबी ने ग्राहक के डेटा पर सेंधमारी के प्रभाव पर साइबरएक्स9 के दावे को खारिज कर दिया।

पीएनबी ने कहा, 'सर्वर एक अलग वीएलएएन (VLAN) सेगमेंट में है और इसके कारण ग्राहक डेटा/एप्लिकेशन प्रभावित नहीं होते हैं। सेंधमारी का मूल्यांकन और इसके प्रभावों को लेकर परीक्षण समय-समय परकिए जाते हैं और उनकी टिप्पणियों का अनुपालन किया जाता है। अब एहतियात के तौर पर इस सर्वर को बंद कर दिया गया है।"

साइबरएक्स9 के अनुसार, 19 नवंबर को इस खामी को संभाला गया था और इस कंपनी ने भारतीय साइबर सुरक्षा निगरानी संस्था सर्ट-इन और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) को घटना की सूचना दी थ।

ताकि आपका घर हो अपना

वर्ष 2022 तक देश के प्रत्येक परिवार को उसका घर देने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से किया है। इस सिलसिले में सरकार गंभीरता से लगातार प्रयास कर रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग से लेकर लैंज बैंक बनाने तक की मुहिम इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। एक मई से देश में नया रियल एस्टेट कानून भी लागू होने जा रहा है। उम्मीद है कि इसके बाद प्रधानमंत्री की इस योजना में और तेजी आएगी।

नरेंद्र मोदी सरकार प्राइवेट बिल्डरों के साथ मिलकर 2 लाख सस्ते घर बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने 350 प्रोजेक्ट लान्च किए हैं। इसमें कुल 38,000 करोड़ का निवेश होगा। सबको घर मुहैया कराने की सरकार की योजना के तहत यह अहम फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में कॉर्पोरेट्स की ओर से यह पहली बड़ी पहल होगी।

घरों की लागत 18 लाख

प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्राइवेट रियल एस्टेट डवेलपर्स के साथ एक बैठक की थी। इस मीटिंग का मकसद उन अड़चनों को दूर करना था ताकि 2022 तक सबको आवास की सरकार की योजना में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी तय हो सके।

कहां बनेंगे कितने घर ?

सबसे ज्यादा एक लाख मकान महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे। उसके बाद एनसीआर में 41921 मकान, गुजरात में 28465, कर्नाटक में 7037 और उत्तर प्रदेश में 6055 मकान बनाए जाएंगे। गोवा, हैदराबाद, मध्यप्रदेश और केरल में 1000 से 2000 घर बनाए जाएंगे। इसी तरह असम, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में 1000 से कम मकान बनाए जाएंगे।

सरकार लैंड बैंक बनाने में जुटी

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सभी सरकारी विभागों को गैर-उपयोगी जमीन की पहचान करने को कहा गया है। खासतौर पर विकसित सरकारी कॉलोनियों में इन जमीनों की तलाश करने को कहा गया है ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स की योजना तैयार की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीमों को गति देने के लिए लैंड बैंक तैयार करना चाहती है। राज्य सरकारों को जमीन की कमी के चलते हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स की योजना बनाने में मुश्किलें आ रही

हैं। इस प्रयास के जरिए पीएमओ को उम्मीद है कि जमीनों की तलाश की जा सकेगी और फिर राज्य सरकार से कहा जाएगा कि वे इन जमीनों की उपलब्धता को लेकर प्रस्ताव भेजें। सभी मंत्रालयों को आदेश दिए गए हैं कि वे एक लिस्ट तैयार करें कि किन कॉलोनियों में नए घरों का निर्माण किया जा सकता है।

शहरी विकास मंत्रालय ने विकसित सरकारी कॉलोनियों में जमीनों का चुनाव शुरू कर दिया है। इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं और इन्हें मंजूरी मिलने में किसी तरह की समस्या आड़े नहीं आएगी। अब तक केंद्र सरकार ने 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90,000 करोड़ रुपए के हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी दी है।

होम लोन पर सब्सिडी

नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए उसे कई तरह से राहत देने की कोशिश की है। मध्य वर्ग को हाउसिंग लोन में 3 से 4 फीसदी तक की छूट देने का फैसला लिया गया है। यह फैसला पहली बार मकान खरीदने वालों पर तो लागू होगा ही, साथ ही वे लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे, जो इस साल एक जनवरी के बाद मकान खरीद चुके हैं। ऐसे लोगों को 12 लाख रुपए तक की लोन राशि पर ब्याज में तीन से चार फीसदी तक की छूट मिलेगी। माना जा रहा है कि इस तरह से मकान खरीदने वालों की ईएमआई में दो हजार रुपए तक की कमी होगी।

शहरी विकास और आवास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि मध्य वर्ग न सिर्फ इनकम टैक्स देकर बल्कि कई दूसरे तरीकों से भी अर्थ व्यवस्था के विकास में मदद करता है। ऐसे में सरकार ने मध्य वर्ग के उन लोगों को मदद देने का फैसला किया है, जो अपने लिए मकान खरीदना चाहता है। इससे पहले सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को ही मकान खरीदने में ब्याज में इस तरह की छूट देती रही है। लेकिन अब पहली बार सालाना 12 लाख और 18 लाख रुपए तक कमाने वालों को भी यह छूट मिलेगी।

12 लाख सालाना आय वालों को 4 फीसदी छूट

आवास मंत्रालय के अनुसार जिन लोगों की सालाना आमदनी 12 लाख रुपए है, उन लोगों

को मकान खरीदने पर लिए, लिए जाने वाले लोन में से नौ लाख रुपए की राशि पर 4 फीसदी की छूट मिलेगी। मसलन, अगर किसी ने 25 लाख रुपए का मकान खरीदा है और 20 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसे 11 लाख रुपए के लोन पर तो पूरा ब्याज चुकाना होगा, लेकिन बाकी नौ लाख रुपए के ब्याज पर उसे 4 पर्सेंट की सब्सिडी मिलेगी। मसलन, अगर उसे 9 फीसदी की दर पर लोन मिला है तो उसे नौ लाख रुपए के लिए सिर्फ पांच फीसदी ही ब्याज चुकाना होगा। उसके लिए शर्त इतनी होगी कि उसने 90 वर्ग मीटर तक का ही मकान खरीदा हो।

18 लाख आय वालों को 3 फीसदी की छूट

इसी तरह से दूसरी कैटेगरी 18 लाख रुपए की सालाना आमदनी वालों की बनाई गई है। ऐसे लोग 110 वर्ग मीटर तक का मकान खरीदकर इस सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। ऐसे लोगों को 12 लाख रुपए के लोन पर ब्याज में तीन फीसदी की छूट मिलेगी। यानी अगर उसने 9 फीसदी की ब्याज दर पर लोन लिया है तो उसे लोन की 12 लाख रुपए की रकम पर ब्याज नौ की बजाय छह फीसदी ही देना होगा।

प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी पड़ेगी

केंद्र सरकार ने साफ किया है कि होम लोन पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत लाभार्थियों को बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी होगी।

सभी बैंकों से लोन पर मिलेगी सुविधा

सरकार का कहना है कि यह सुविधा सभी बैंकों से लोन लेने वालों पर लागू होगी। अगर किसी व्यक्ति ने एक जनवरी के बाद मकान खरीद लिया है और वह इस श्रेणी में आता है तो उसे भी इसका फायदा मिलेगा। उसे सिर्फ अपने बैंक को इस सुविधा को लेने की जानकारी देनी होगी। उसके बाद बैंक उसके दस्तावेजों की जांच करके नए सिरे से ईएमआई केलकुलेट करेगा। सरकार ने नेशनल हाउसिंग बैंक और हुडको को नोडल एजेंसी बनाया है।

सस्ते घर में मददगार जीएसटी

शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू ने सस्ते मकानों के लिए जीएसटी प्रणाली के तहत सर्विस टैक्स में छूट देने की वकालत की है ताकि कम लागत वाले मकानों की कीमतें नहीं बढ़ें। नायडू ने रीयल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई के एक कार्यक्रम में राज्यों से कहा कि वे किफायती आवासीय परियोजना के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट दें तथा अन्य के लिए इसे युक्तिसंगत बनाएं। उन्होंने आश्वस्त किया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली से कीमतें नहीं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि, किफायती आवास खंड को सेवा कर से छूट है। किफायती आवास खंड को बजट में बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया गया है और इससे खरीदारों में नकदी उपलब्धता बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।

डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन के आपात उपयोग की मंजूरी दी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने बुधवार को भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन के आपात उपयोग के लिए मंजूरी दे द। भारत बायोटेक ने इसे स्वदेश विकसित टीके तक वैश्विक पहुंच को व्यापक बनाने की दिशा में अहम कदम बताया।

इससे पहले डब्ल्यूएचओ के तकनीकी परामर्शदाता समूह (टीएजी) ने इसकी सिफारिश की थ। उसने 26 अक्टूबर को टीके को आपात उपयोग के लिए सूचीबद्ध करने के लिहाज से अंतिम 'जोखिम-लाभ मूल्यांकन" करने के लिए कंपनी से अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगे थे।

डब्ल्यूएचओ के इस निर्णय का तात्पर्य है कि स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन कोरोना वायरस बीमारी से सुरक्षा के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करता है। साथ ही यह उन भारतीयों द्वारा विदेश यात्रा के बारे में अनिश्चितता को भी काफी हद तक दूर करता है, जिन्हें कोवैक्सीन का टीका लगाया गया है।

इस बीच भारत बायोटेक ने कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने कोवैक्सीन की उपयोग अवधि (शेल्फ लाइफ) को निर्माण की तारीख से 12 महीने तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारत बायोटेक को शुरुआत में कोवैक्सीन की बिक्री और वितरण के लिए छह महीने की उपयोग अवधि की अनुमति दी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर नौ महीने कर दिया गया था।

कोवैक्सीन को लाइसेंस देने के लिए डब्ल्यूएचओ का आभार जताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह उपलब्धि 'मोदी जी के संकल्प और सक्षम नेतृत्व की बानगी है, यह लोगों के विश्वास की कहानी है और यह आत्मनिर्भर भारत की दिवाली है।"

डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट किया, 'डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन (भारत बायोटेक द्वारा विकसित) टीके को आपात उपयोग के लिए सूचीबद्ध किया है। इस तरह कोविड-19 की रोकथाम के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त टीकों की संख्या में इजाफा हुआ है।"

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि उसके द्वारा बनाया गया टीएजी, जिसमें दुनियाभर के नियामक विशेषज्ञ हैं, पूरी तरह से आश्वस्त है कि कोवैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ रक्षा करने संबंधी उसके मानकों पर खरी उतरती है और इस टीके के लाभ इसके जोखिमों से कहीं अधिक है, अतः इसका उपयोग किया जा सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि एजेंसी के 'स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इम्युनाइजेशन (एसएजीई) ने भी कोवैक्सीन की समीक्षा की

और दो खुराक में इस टीके के इस्तेमाल की अनुशंसा की है। इसे 18 वर्ष और अधिक आयु के सभी लोगों को चार हफ्ते के अंतराल पर दिया जा सकता है।

हालांकि डब्ल्यूएचओ की ओर से एक ट्वीट में कहा गया, 'कोवैक्सीन से गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वे गर्भावस्था में टीके के प्रभावी या सुरक्षित होने के लिहाज से अपर्याप्त हैं। गर्भवती महिलाओं में टीके के अध्ययन की योजना है।"

डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉ पूनम खेत्रपाल सिंह ने ट्वीट किया, 'भारत को उसके स्वदेश विकसित कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन को आपात उपयोग के लिए सूचीबद्ध किए जाने के लिए बधाई।"

भारत बायोटेक ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उसके कोविड-रोधी कोवैक्सीन टीके को आपात उपयोग के लिए सूचीबद्ध किया जाना स्वदेश विकसित टीके तक व्यापक वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कंपनी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ), पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (पाहो) और गावी कोवैक्स सुविधा भी दुनियाभर में देशों को वितरण के लिए कोवैक्सीन टीके खरीद सकेंगे।

भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा ऐल्ला ने कहा, 'डब्ल्यूएचओ द्वारा मंजूरी भारत के व्यापक तौर पर दिए जाने वाले, सुरक्षित और प्रभावी कोवैक्सीन टीके तक वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

भारत बायोटेक की संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा एल्ला ने कहा, 'कोवैक्सीन के लिए डब्ल्यूएचओ की मंजूरी भारत बायोटेक में काम करने वाले सभी लोगों और हमारे साझेदारों के अत्यधिक प्रयासों को समर्थन है। यह हमारे लिए वैश्विक स्तर पर सार्थक प्रभाव पैदा करने के लिहाज से एक अवसर भी है।"

इसमें बताया गया कि कोवैक्सीन, दोनों खुराक लेने के बाद किसी भी गंभीरता वाले कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ 78 फीसदी प्रभावी पाई गई है। यह कम और मध्यम आय वाले देशों के लिए अत्यंत ही सुलभ है, क्योंकि इसकी भंडारण जरूरतें काफी आसान हैं। डब्ल्यूएचओ की घोषणा से पहले एक सूत्र ने बताया था, 'डब्ल्यूएचओ के तकनीकी परामर्शदाता समूह ने कोवैक्सीन को आपात उपयोग के लिए सूचीबद्ध का दर्जा देने की सिफारिश की है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में जी-20 शिखर सम्मेलन में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ। टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस से मुलाकात की थ।

डब्ल्यूएचओ का तकनीकी परामर्शदाता समूह एक स्वतंत्र सलाहकार समूह है, जो डब्ल्यूएचओ को यह सिफारिश करता है कि क्या किसी कोविड-19 रोधी टीके को आपात इस्तेमाल के लिए सूचीबद्ध (ईयूएल) प्रक्रिया के तहत आपात उपयोग के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है या नहीं।

कोवैक्सीन ने लक्षण वाले कोविड-19 रोग के खिलाफ 77।8 प्रतिशत प्रभाव दिखाया है और वायरस के नए डेल्टा स्वरूप के खिलाफ 65।2 प्रतिशत सुरक्षा दर्शाई है।

कंपनी ने जून में कहा था कि उसने तीसरे चरण के परीक्षणों से कोवैक्सीन के प्रभाव का अंतिम विश्लेषण समाप्त किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 38 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय समझौते हैं, जो वर्तमान में कोवैक्सीन को मान्यता देते हैं। डब्ल्यूएचओ की मंजूरी से दुनिया भर के कई अन्य देशों को टीका लगाने वालों के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए प्रेरित करने की संभावना है।

भारत अब तक देश भर में कोवैक्सीन की 12।14 करोड़ खुराक दे चुका है। डब्ल्यूएचओ का निर्णय वैक्सीन के वैश्विक उपयोग के लिए ईयूएल मूल्यांकन शुरू करने के चार महीने से अधिक समय बाद आया है।

शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया कि बुधवार को ईयूएल विस्तृत वैज्ञानिक जांच के बाद आई है। डब्ल्यूएचओ ने भारत बायोटेक से कोवैक्सीन के आकलन से संबंधित जानकारी बीते पांच जुलाई से कम से कम नौ बार मांगी थ।

ईयूएल कोविड-19 टीकों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता का एक वैज्ञानिक मूल्यांकन है, जो विभिन्न देशों को इन उत्पादों के आयात और प्रशासन के लिए अपने खुद के नियामक अनुमोदन को तेजी से निगरानी या जांच करने की अनुमति देता है।

गौरतलब है कि सीरम इंस्टिट्यूट का कोविशील्ड और भारत बायोटेक का कोवैक्सीन देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान का हिस्सा है और कुछ खबरें आई थीं कि जिन भारतीयों ने कोवैक्सीन की खुराक ली हैं उन्हें विदेश यात्रा करने में परेशानी आ रही है, क्योंकि इस टीके को मान्यता नहीं मिली है। मालूम हो कि भारतीय दवा महानियंत्रक डीसीजीआई ने जनवरी में दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी पुणे स्थित सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड तथा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी थ।

भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर कोवैक्सीन का विकास किया है। वहीं, सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने 'कोविशील्ड" के उत्पादन के लिए ब्रिटिश-स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की है।

सिविल सेवा, बदलाव की हिमायत पर, इतना हंगामा है क्यों बरपा ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सिविल सेवाओं को लेकर जिस तरह के रुख का इज़हार किया उस पर नौकरशाही से लेकर मीडिया तक में हलचल मच गई है। सोशल मीडिया के मंचों पर रिटायर्ड सिविल सेवकों में इस सवाल पर तगडी बहस चल पड़ी है। इस बहस में बड़ी बहस प्रतिबद्ध नौकरशाही (कमिटेड ब्यूरोक्रेसी) और चारक नौकरशाही (लॉयल ब्यूरोक्रेसी) के सवाल पर हो रही है। इसके समानांतर इन सेवाओं में लेटरल इंट्री भी बहस का मुद्दा बना हुआ है।

सरकार की तरफ से केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव और निदेशक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए 30 पदों का विज्ञापन प्रकाशित किया गया। विज्ञापित पदों में से 3 संयुक्त सचिव पद के लिए हैं जबकि 27 पद निदेशकों के हैं। इन पदों पर नियुक्ति 3 से लेकर 5 वर्षों की संविदा के आधार पर होनी है। इन नियुक्तियों में आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं हैं। पिछले साल भी, लिटेरल इंट्री के जरिए 9 पदों पर भर्ती की गई थी जिसमें चुनी गई काकोली घोष ने सेवा को ज्वाइन ही नहीं किया जबकि अरुण गोयल ने बाद में पद से इस्तीफा देकर वापस निजी क्षेत्र में काम शुरू कर दिया।

भारत में बहुतों का मानना है कि पिछले दशकों में सिविल सेवा की दशा और दिशा पर बहुत असर पड़ा है और उसकी चमक फीकी पड़ी है। ये भी माना जा रहा है कि देश में नौकरशाही की प्रतिबद्धता और साख सवालों के घेरे में आ गई है। प्रशासनिक सुधार आयोग और नीति आयोग की कमेटी ने भी इन मसलों को लेकर सरकार को भेजी अपनी सिफारिशों में इन मुद्दों को उठाया है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि, समय के साथ सिविल सेवा में जिस तरह के बदलाव की अपेक्षा थी वो नहीं की गई और इसी कारण से बदलती परिस्थितियों के साथ इस सेवा की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे। आजादी के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू अखिल भारतीय सेवाओं को खत्म करना चाहते थे लेकिन तत्कालील गृह मंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल ने इन सेवाओं को बरकरार रखने की जोरदार वकालत की और ये सेवाएं बनी रहीं।

नीति आयोग की संस्तुतियां

नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल से ही सरकार ने सिविल सेवाओं में सुधार के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने साल 2018 में अपनी रिपोर्ट में इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया। THE STRATEGY FOR NEW INDIA @ 75 नाम से सौंपी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 तक नए भारत के विकास के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सिविल सेवा में भर्ती, प्रशिक्षण और उनके कामकाज की समीक्षा के लिए व्यापक सुधार की जरूरत है। सरकार ने भी मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के तहत सिविल सेवकों के ऐसे प्रशिक्षण पर बल दिया जिससे उनमें रचनाधार्मिता का विकास होने के साथ ही वे दूरदर्शी, प्रगतिशील, ऊर्जा से भरपूर और बेहतर पेशेवर बन सकें।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस संदर्भ में कई सिफारिशें कीं। साल 2005 में गठित इस आयोग ने अपनी सिफारिशें 2009 में सरकार

को सौंपी। प्रशासन से जुड़े विभिन्न आयामों पर इसने करीब 15 रिपोर्टें सरकार को सौंपी और 1514 संस्तुतियां कीं जिसमें से 1183 संस्तुतियों को सरकार ने स्वीकार कर लिया और विभिन्न मंत्रालयों को इन पर अमल के लिए भेज दिया। नीति आयोग के अनुसार, बहुत सी संस्तुतियों पर अभी भी अमल नहीं किया गया है।

प्रभावी सिविल सेवा की राह में चुनौतियां

इस रिपोर्ट में प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह सिविल सेवा की राह में कई तरह की चुनौतियों का जिक्र किया गया है। इनमें ओहदे और कौशल के बीच असमानता का सबसे पहले जिक्र है जिसमें मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में विशेषज्ञता के अभाव का उल्लेख किया गया है। इसी तरह से सिविल सेवाओं में विभिन्न तरह के विशेषज्ञों की जरूरत का जिक्र भी रिपोर्ट में है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि, हर पांच साल में इस बात की समीक्षा की जानी चाहिए कि किस तरह के लोकसेवककों की जरूरत है और उसी के अनुरूप भर्ती होनी चाहिए।

पूर्व सिविल सेवक और कंसल्टिंग फर्म के संस्थापक प्रबीर झा के अनुसार, नौकरशाही में कौन इस तरह के बदलाव लाएगा जबकि इस बदलाव की जिम्मेदारी खुद उन्हीं लोगों के हाथ में है जिन्हें बदला जाना है। वे सुझाव देते हैं कि सबसे पहले तो अंकों के आधार पर सेवाओं का आवंटन नहीं होना चाहिए। शीर्ष रैंकिंग वाले उम्मीदवार आमतौर पर आईएएस, आईएफएस या आईपीएस जैसी सेवाओं में जाने का विकल्प चुनते हैं लेकिन कई बार उनके अंदर इस सेवाओं के लिए अपेक्षित कौशल नहीं होता। प्रशिक्षण के दौरान ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं जिनसे उम्मीदवार के कौशल को आंका जा सकता है और उसी के अनुरूप उसे सेवा चुनने का मौका दिया जाना चाहिए।

दूसरी समस्या, सिविल सेवक की स्थायी नौकरी और खुद ब खुद होने वाला प्रमोशन है। बेहतरीन और साहसी अफसर आज की जरूरत हैं चाहे वे अलोकप्रिय ही क्यों ना हों। लेकिन सुरक्षित नौकरी ने इन सेवाओं मे कहीं ना कहीं अक्षम और भ्रष्ट किस्म के अफसरों को बढ़ावा दिया है। उनका कहना है कि, सिविल सेवकों के प्रमोशन में हर स्तर पर उनके कामकाज की ठोस समीक्षा होनी चाहिए उसके बाद ही उन्हें प्रमोशन दिया जाना चाहिए।

उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिविल सेवकों को राजनेताओं के साथ मिलकर काम करना होता है। इसके बुरे नतीजे देखे जा रहे हैं। इससे बचने के लिए सिविल सेवाकों के करियर मसलों को देखने के लिए सिविल सेवा बोर्ड होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि शीर्ष पदों पर बैठे लोकसेवकों की कार्यप्रणाली कहीं ज़्यादा पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए।

लिटेरल इंट्री

लिटेरल इंटट्री के सवाल पर विशेषज्ञों की राय़ अलग-अलग है लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट में साफ है कि आज प्रासंगिकता विशेषज्ञ सेवाओं की है। तमाम विभाग ऐसे हैं जो कोई विशेषज्ञ या पेशेवर ही संभाल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार आज स्पेशलिस्ट अफसर और जनरलिस्ट अफसर में फर्क करने और उनमें संतुलन बनाने का वक्त है। मौजूदा तंत्र ऐसे अफसर तैयार करता है जो सिर्फ सामान्य प्रशासन के लिए ही उपयुक्त हैं और ज्यादातर सेवाओं के लिए वे अप्रासंगिक हो चुके हैं।

बजट 2022: वित्त मंत्री के चौथे बजट में जनता को क्या मिलेगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नरेंद्र मोदी सरकार का दसवां बजट पेश करने वाली हैं। अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा क्योंकि धीरे-धीरे कोविड-19 की तीसरी लहर से बाहर निकल रहा है और बढ़ते मुद्रास्फीति दबाव का सामना कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार सुबह बजट को मंजूरी दे दी है। विशेष रूप से, विशेषज्ञों का मानना है कि 2020 में महामारी के प्रकोप के बाद आर्थिक व्यवधान के बाद अपर्याप्त राहत पर बढ़ती सार्वजनिक आलोचना के बीच सीतारमण किफायती आवास और उर्वरक के लिए उच्च सब्सिडी के अलावा सड़कों और रेलवे पर अधिक खर्च की घोषणा करेंगी।

जबकि देश की राजकोषीय स्थिति अपेक्षा से अधिक स्वस्थ दिखती है, औसत करदाता को बड़ी राहत मिलने की संभावना नहीं है।

प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के नेतृत्व वाले एक दल द्वारा तैयार 2021-22 की आर्थिक समीक्षा में आगे कहा गया कि 2020-21 में अर्थव्यवस्था को दिए गए वित्तीय समर्थन के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के कारण राजकोषीय घाटा और सरकारी ऋण बढ़ गया। हालांकि, 2021-22 में अब तक सरकारी राजस्व में जोरदार उछाल देखने को मिला है।

समीक्षा के अनुसार, सरकार के पास समर्थन बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर पूंजीगत व्यय बढ़ाने की वित्तीय क्षमता है। समीक्षा में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है और यह 2022-23 की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है।

वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने सोमवार को पत्रकारों बताया कि राजस्व प्राप्तियों में मजबूत पुनरुद्धार, जो एक साल पहले से अप्रैल-नवंबर की अवधि में 67 फीसदी बढ़ा, का मतलब है कि सरकार के पास 'जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय स्थान है।"

इसके बजाय, मोदी सरकार द्वारा स्थानीय उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों को बढ़ावा देने और परिवहन और स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क पर खर्च बढ़ाने की संभावना है।

बजट से एक दिन पहले सोमवार को एक महत्वपूर्ण आर्थिक खबर सार्वजनिक की गई। यानी पिछले कुछ वर्षों के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों में संशोधन।

अच्छी खबर? मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था अनुमानित से कम संकुचित हुई। सरकार द्वारा जारी पहले संशोधित अनुमानों के अनुसार, जीडीपी 2020-21 में 7.3% संकुचन के अनंतिम अनुमान की तुलना में 6.6% सिकुड़ी।

जो इतनी अच्छी खबर नहीं है? 2019-20 के लिए जीडीपी की वृद्धि को 4% के पहले के अनुमान से संशोधित कर 3.7% कर दिया गया था। यह इस साल का दूसरा संशोधित अनुमान है।

पांच राज्यों में बजा चुनावी बिगुल, नेताओं ने कसी कमर

विवेकानंद बाईजोडिया, चीफ रिपोर्टर

सपा गठबंधन की सरकार बनी तो राज्य में कोई किसान विरोधी कानून लागू नहीं होने देंगे: अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी से किसानों को सावधान रहने की अपील करते हुए शुक्रवार को कहा कि सत्तारूढ़ दल (भाजपा) की सरकार ने सिर्फ वोट की खातिर अपने विवादास्पद कृषि कानून वापस लिए हैं। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि यदि उनके (सपा के) गठबंधन की सरकार बनी तो वे राज्य में इस तरह के किसी किसान विरोधी कानून को लागू नहीं होने देंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) प्रमुख जयंत चौधरी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह कहा। रालोद, सपा के साथ गठबंधन कर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ रहा है।

विधानसभा चुनाव से पहले, भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाताओं से संपर्क साध रही है। इस क्षेत्र से समुदाय के सदस्यों ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर साल भर चले प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। भाजपा नेताओं ने रालोद प्रमुख से भाजपा से हाथ मिलाने को भी कहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दिल्ली में जाट नेताओं के साथ एक बैठक की थी। जयंत ने कहा कि सपा के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन बहुत मजबूत है और किसानों के हितों के लिए काम करने का लक्ष्य रखता है।

अखिलेश ने कहा, 'भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन वह किसान विरोधी तीन कानून ले आई। किसानों ने सरकार को इन कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। भाजपा ने वोट की खातिर इन कानूनों को वापस लिया। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कोई चीज कहे बगैर कानून ले आती है।"

पूर्व मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि सत्ता में आने पर उनकी पार्टी राज्य में इस तरह का कोई कानून लागू नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि जयंत, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और दिवंगत किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत द्वारा किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों की पैरोकारी को आगे बढ़ा रहे हैं।

जयंत ने कहा कि पहले लोगों को संदेह था कि क्या दोनों दलों के बीच गठबंधन होगा। उन्होंने अपने दादा चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए कहा, 'हमारा मेल काफी पहले हो गया था। हम प्रदेश का विकास करना चाहते हैं और गठबंधन किया क्योंकि हम चौधरी चरण सिंह की लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं।"

जयंत ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए न्योते के बारे में कहा कि उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, जयंत ने कहा, 'मैंने उनके न्योते को गंभीरता से नहीं

लिया है। पश्चिमी यूपी केवल जाटों का नहीं है। वे और विभाजन पैदा करना चाह रहे हैं। वो असली मुद्दों के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन 80-20 प्रतिशत, जिन्ना, औरंगजेब करते हैं। हम निर्णय ले चुके हैं और इसी पर कायम रहेंगे।"

अखिलेश संवाददाता सम्मेलन के लिए मुजफ्फरनगर देर से पहुंचे। उन्होंने इससे पहले दिन में दावा किया था कि वह दिल्ली में फंस गए थे क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी गई।

उन्होंने एक ट्वीट में पृष्ठभूमि में एक हेलीकॉप्टर के साथ अपनी तस्वीर साझा की। उन्होंने ट्वीट में कहा, 'मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोककर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है। जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहां से रवाना हुए हैं। हारती हुई भाजपा की ये हताशा भरी साज़िश है। जनता सब समझ रही है।"

अखिलेश यादव पाकिस्तान के समर्थक, जिन्ना के उपासकः योगी आदित्यनाथ

इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें पाकिस्तान का समर्थक और 'जिन्ना का उपासक" करार दिया।

योगी ने किसी का नाम लिए बिना एक ट्वीट में कहा 'वे 'जिन्ना" के उपासक हैं, हम 'सरदार पटेल" के पुजारी हैं। उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्योछावर करते हैं।"

मुख्यमंत्री का इशारा सपा प्रमुख के पाकिस्तान संबंधी बयान और उस टिप्पणी की ओर था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना की सराहना करते हुए कहा था कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था।

गौरतलब है कि सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक अखबार को दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि भारत का असल दुश्मन चीन है, पाकिस्तान तो राजनीतिक दुश्मन है और भाजपा वोट बैंक की राजनीति के लिए सिर्फ पाकिस्तान पर ही निशाना साधती है। इस मुद्दे पर एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अखिलेश पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट में कहा था, 'उत्तर प्रदेश के चुनाव में पाकिस्तान के निर्माता जिन्ना का नाम क्यों लिया जा रहा है। अगर राजनीति करनी है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्ना का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि किसानों के गन्ना का नाम लिया जाना चाहिए।"

भाजपा ने ज़ारी की 91 उम्मीदवारों की एक और सूची

भाजपा ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के लिए 91 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। इस सूची में पार्टी के राज्य सरकार के मंत्रियों राजेंद्र प्रताप सिंह मोती, रमापति शास्त्री, सिद्धार्थ नाथ सिंह, जय प्रताप सिंह, उपेंद्र तिवारी, नंदकुमार गुप्ता नंदी, सूर्य प्रताप शाही समेत 13 मंत्रियों को उम्मीदवार घोषित किया गया है।

हालांकि, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा को इस बार पार्टी ने मौका नहीं दिया है। भाजपा ने 91 उम्मीदवारों की इस सूची में लगभग 20 विधायकों का टिकट काटा है। इस बार बहराइच की कैसरगंज विधानसभा सीट से मुकुट बिहारी वर्मा की जगह उनके पुत्र गौरव वर्मा पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं।

अयोध्या जिले के बीकापुर क्षेत्र में विधायक शोभा देवी की जगह इस बार पार्टी ने उनके बेटे डॉक्टर अमित सिंह चौहान को मौका दिया है।

अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने एक बार फिर वेदप्रकाश गुप्ता पर भरोसा जताया है जो 2017 में भाजपा के टिकट पर इस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे।

पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक सूची के मुताबिक, मोती सिंह प्रतापगढ़ जिले की पट्टी, सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से, रमापति शास्त्री गोंडा जिले की मनकापुर (अनुसूचित जाति), जयप्रताप सिद्धार्थनगर की बांसी, सतीश द्विवेदी-इटवा, उपेंद्र तिवारी बलिया जिले के फेफना, नंदी इलाहाबाद दक्षिण, शाही पथरदेवा, सुरेश पासी जगदीशपुर (अजा), पल्टू राम बलरामपुर (अजा), जयप्रकाश निषाद देवरिया के रुद्रपुर और गिरीश चंद्र यादव-जौनपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे।

पिछली बार संतकबीरनगर के धनघटा से चुनाव जीतने वाले राज्य मंत्री श्रीराम चौहान को इस बार गोरखपुर जिले की खजनी विधानसभा सीट से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी को पार्टी ने देवरिया से उम्मीदवार बनाया है। पिछले दिनों भाजपा में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष राय को अंबेडकरनगर जिले की जलालपुर सीट से टिकट दिया गया है।

इसी प्रकार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राकेश सचान को भोगनीपुर से उम्मीदवार बनाया गया है।

इसके साथ ही भाजपा ने 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 294 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा उत्तर प्रदेश में अपना दल-एस और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है।

बहुजन समाज पार्टी ने चौथे चरण के चुनाव के लिए 53 उम्मीदवारों की घोषणा की

बसपा ने उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 53 उम्मीदवारों की घोषणा की। चौथे चरण में नौ जिलों की 59 सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होगा।

शुक्रवार को बसपा प्रमुख मायावती ने चौथे चरण के 53 उम्मीदवारों की सूची ट्विटर पर साझा की।

उन्होंने ट्वीट किया, 'उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार धर्म व जाति की राजनीति हावी है व मीडिया में भी ऐसी खबरें भरी पड़ी रहती हैं, उससे ऐसा लगता है कि यह सब सपा व भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत के तहत ही हो रहा है और वे चुनाव को हिंदू-मुस्लिम व जातीय नफरती रंग देना चाहती हैं। जनता सतर्क रहे।"3

बसपा की इस सूची में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। बसपा ने अपनी सूची में दलितों, पिछड़ों और अगड़ों के साथ ही अल्पसंख्यकों का भी संतुलन बनाया है।

जारी सूची के मुताबिक पीलीभीत के बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री अनीस खां उर्फ फूल बाबू को उम्मीदवार बनाया गया है जबकि लखीमपुर खीरी जिले की निघासन सीट पर बसपा ने मनमोहन मौर्य को मौका दिया है।

पिछले वर्ष तीन अक्टूबर को निघासन क्षेत्र में किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार समेत आठ लोग मारे गए थे। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और उसके सहयोगियों को आरोपी बनाया गया जो इस समय जेल में निरुद्ध हैं।

बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस मामले में किसानों के पक्ष में बोलते हुए सत्तारूढ़ भारतीय

जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया था।

बसपा की सूची में लखनऊ जिले की सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं जिनमें चार उम्मीदवार मुस्लिम हैं।

लखनऊ की मलिहाबाद सुरक्षित सीट से जगदीश रावत, बख्शी का तालाब से सलाउद्दीन सिद्दीकी, सरोजनीनगर से मोहम्मद जलीस खां, लखनऊ पश्चिम से मोहम्मद कायम रजा खान, लखनऊ उत्तरी से मोहम्मद सरवर मलिक, लखनऊ पूर्वी से आशीष कुमार सिन्हा, लखनऊ मध्य से आशीष चंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ कैंट से अनिल पांडेय और मोहनलालगंज सुरक्षित से देवेंद्र कुमार सरोज को उम्मीदवार बनाया गया है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली जिले में बसपा ने पांच विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस जिले में छह विधानसभा क्षेत्र हैं।

उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा।

20 फरवरी को तीसरे चरण में 59 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण में 59 सीटों पर, 27 फरवरी को पांचवें चरण में 61 सीटों पर, तीन मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और सात मार्च को सातवें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा।

पंजाब विधानसभा चुनाव

पंजाब की धुरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार एवं मौजूदा विधायक दलवीर सिंह गोल्डी ने आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवंत मान को विकास कार्यों के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती देते हुए दावा किया कि लोगों से कहने के लिए मान के पास कुछ नहीं है।

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने धुरी सीट से संगरूर के पूर्व विधायक प्रकाश चंद गर्ग को मैदान में उतारा है।

धुरी, संगरूर संसदीय सीट के विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। मान संगरूर से दो बार के सांसद हैं। वहीं, गोल्डी (40) पिछले पांच वर्ष में धुरी निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कई विकास कार्यों पर आश्रित हैं।

गोल्डी ने कहा, 'हमने निर्वाचन क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं और मैं पिछले पांच साल से क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहा हूं।"

गोल्डी छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं और 2005-06 में 'पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट काउंसिल" के अध्यक्ष थे।

धुरी में मान से मुकाबले के सवाल पर गोल्डी ने कहा, 'मैं उन्हें एक कॉमेडियन के तौर पर देखता हूं, एक गंभीर राजनेता के रूप में नहीं।"

गोल्डी ने कहा कि मान अपने भाषणों के दौरान लोगों को 'मूर्ख" बनाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार का बखान कर रहे हैं।

'आप" ने एक सर्वेक्षण करने के बाद मान को पंजाब में अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। गोल्डी ने कहा, 'मान ने पंजाब के लिए किसी योजना की कभी कोई बात नहीं की।"

उनका इशारा घटते भूमिगत जल स्तर की ओर था, क्योंकि धुरी 'डार्क जोन" में आता है, जिसके बारे में 'आप" उम्मीदवार ने कभी बात नहीं की है।

कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने कहा, 'मान ने कभी खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में भी कोई बात नहीं की। मुझे नहीं लगता कि वह धुरी निर्वाचन क्षेत्र को लेकर गंभीर हैं। अगर वह हैं, तो उन्हें सांसद पद से इस्तीफा देकर धुरी से चुनाव लड़ना चाहिए।"

गोल्डी ने कहा कि अगर उन्होंने राज्य के लोगों के लिए कुछ किया होता, तो उन्हें पंजाब के लोगों को 'दिल्ली मॉडल" के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती।

गोल्डी ने कहा कि मान को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के अलावा धुरी में कभी नहीं देखा गया। एक सांसद होने के नाते वह धुरी के लोगों के लिए कुछ कर सकते थे।

गोल्डी ने मान को इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए किए गए किसी भी विकास कार्य का लेखा-जोखा देने के लिए उनके साथ एक खुली बहस करने की चुनौती दी।

उन्होंने कहा, 'मैं उन्हें खुली बहस की चुनौती देता हूं। वह अपने पांच सर्वश्रेष्ठ विकास कार्य बताएं और मैं भी अपने पांच सर्वश्रेष्ठ विकास कार्य बताऊंगा।""

कांग्रेस उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में 'धुरी मेरी मिट्टी, धुरी मेरा परिवार" चुनाव अभियान चला रहे हैं और घर-घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह धुरी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 'आप" और शिअद के उम्मीदवार 'बाहरी" हैं।

गोल्डी ने 2017 विधानभा चुनाव में 'आप" उम्मीदवार जसवीर सिंह को 2,811 मतों से मात देकर, जीत दर्ज की थी। धुरी मुख्य रूप से एक ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें 74 गांव शामिल हैं। यहां 77,000 महिलाओं सहित 1.63 लाख मतदाता हैं।

गोवा विधानसभा चुनाव

चार विधानसभा सीटों पर नेताओं की बगावत भाजपा के लिए मुसीबत बनी

गोवा विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर स्थानों पर असंतुष्ट नेताओं को काबू में करने में सफलता पाई है लेकिन पणजी समेत चार सीटें पार्टी के लिए चिंता का कारण बनी हुई हैं।

पणजी में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिवंगत कद्दावर नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर, सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार अतानासियो मोंसेरेट के विरुद्ध निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं।

मोंसेरेट 2019 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। उत्पल ने दावा किया है कि उनके मन में भाजपा ही है लेकिन वह इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं ताकि कोई गलत व्यक्ति उस सीट से न जीत जाए जिसका प्रतिनिधित्व उनके (उत्पल) पिता कर चुके हैं। उन्होंने संभवतः मोंसेरेट के खिलाफ दर्ज गंभीर मामलों की ओर इशारा किया।

मांड्रेम में लक्ष्मीकांत पारसेकर ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है जो पार्टी की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष थे। अब वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दयानन्द सोपते के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं जिन्होंने उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में 2017 में शिकस्त दी थी।

संगुएम सीट पर सावित्री कवलेकर ने बगावत कर दी है और अब वह भाजपा के उम्मीदवार सुभाष फलदेसाई के विरुद्ध लड़ रही हैं। कवलेकर, पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत कवलेकर की पत्नी हैं और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई थीं।

कंभरजुआ सीट पर भाजपा को सिद्धेश को शांत रखने में सफलता मिली है जो केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक के बेटे हैं। टिकट न मिलने से नाराज सिद्धेश ने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया था।

हालांकि, वर्तमान विधायक पांडुरंग मडकईकर की पत्नी और भाजपा प्रत्याशी जैनिता मडकईकर को पूर्व सहयोगी रोहन हरमलकर के खिलाफ लड़ना होगा जो कंभरजुआ से निर्दलीय उम्मीदवार हैं।

उत्तराखंड: कांग्रेस घोषणापत्र जारी, महिलाओं को पुलिस में 40 फीसदी नौकरियों का वादा

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को उत्तराखंड के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किया।

इसमें पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने, चार लाख लोगों को नौकरी देने और 'पर्यटन पुलिस" बल के गठन का वादा किया गया है।

घोषणापत्र को 'उत्तराखंड स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र" नाम दिया गया है। घोषणापत्र में 40 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता देने और रसोई गैस की कीमत 500 रुपये करने का वादा किया गया है।

प्रियंका ने ऑनलाइन रैली में घोषणापत्र जारी किया, जिसका सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीधा प्रसारण किया गया।

उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार पर पिछले पांच वर्ष में कोई काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने लोगों से अपने वोट को गंभीरता से लेने को कहा। उन्होंने वोट को परिवर्तन लाने के लिए मतदाताओं का 'सबसे शक्तिशाली हथियार" बताया।

प्रियंका ने कहा, 'पांच साल में मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। हम अब भी केवल हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं, जो इससे पहले सत्ता में थी। उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि काम करने की उनकी कोई मंशा ही नहीं थी।"

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) की महासचिव ने कहा, 'कांग्रेस बदलाव ला सकती है, लेकिन तब, जब आप अपने अधिकारों और अपने बच्चों के भविष्य की खातिर लड़ने के लिए जागेंगे।"

प्रियंका ने कहा, 'तथाकथित डबल इंजन के इंजन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण काम करना बंद कर दिया है।"

उन्होंने कहा कि देशभर में गन्ना किसानों की बकाया राशि 14,000 करोड़ रुपये है, जिसे आसानी से अदा किया जा सकता था यदि प्रधानमंत्री के लिए दो हवाई जहाज खरीदने में खर्च किए गए 16,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता।

प्रियंका ने कहा, 'कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश अपने सबसे बड़े संकट से गुजरा, क्योंकि केंद्र ने दूसरे देशों को ऑक्सीजन और टीके दोनों का निर्यात किया।"

उन्होंने कहा कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। प्रियंका ने कहा, 'मुझे बताया गया था कि हीरा सस्ता हो गया है, लेकिन दवाएं महंगी हो गई हैं।"

उन्होंने लोगों को राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे वादों में न फंसने की सलाह दी और कहा कि अगर उन्हें अपना जीवन बदलना है और अपनी स्थिति में सुधार चाहिए तो वे उन दलों से उनके 'रोडमैप" के बारे में पूछें।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार का आगाज करते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर पर जमकर निशाना साधा और उन्हें दलित विरोधी, गुंडों की पार्टी और नफरत फैलाने वाली पार्टी बताया।

मायावती ने आरोप लगाया, 'कांग्रेस, दलितों गरीबों को लुभाने के लिए नाटक कर रही है। सपा की सरकार में गुंडा, बदमाश, माफिया और लूट-खसोट करने वालों का राज रहता है। वहीं भाजपा नीत सरकार में धर्म के नाम पर हमेशा तनाव और नफरत का वातावरण रहा है।"

मीडिया को जातिवादी बताते हुए मायावती ने दावा किया, 'हमारी पार्टी अपने बूते पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मीडिया के सभी दावे 2007 की तरह एक बार फिर गलत साबित होंगे।"

बसपा सुप्रीमो ने बुधवार को आगरा में अपनी पहली चुनावी जनसभा से पार्टी के प्रचार की शुरुआत की। जनसभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा, 'आजादी के बाद सिर्फ कांग्रेस की सरकार रही है लेकिन गलत नीतियों और गलत कार्यप्रणाली के कारण वह केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गई।"

कांग्रेस पर दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग का विरोध होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, 'केंद्र की सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। न ही इसने पिछड़े वर्ग के आरक्षण से जुड़ी मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कीं।"

उन्होंने कहा कि बसपा ने अपने कड़े संघर्ष और प्रयासों से इन सिफारिशों को लागू कराया।

पूर्ववर्ती सपा सरकार पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा, 'सपा सरकार के कारण हर स्तर पर दलितों और ओबीसी के साथ सौतेला व्यवहार होता है। उसने सत्ता में आने पर हमारी सरकार में दलित एवं अन्य संतों/महापुरुषों के नाम पर जिन जिलों के नाम पर रखे गए थे उन्हें बदल दिया।"

वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों और दलितों को लुभाने का प्रयास करते हुए मायावती ने कहा, 'आपको बता दूं कि संसद में पदोन्नति में आरक्षण के लिए पेश विधेयक का सपा ने विरोध किया था और उसकी प्रति फाड़ दी थी।"

राज्य की मौजूदा भाजपा नीत सरकार पर निशाना साधते हुए बसपा नेता ने कहा, 'इनका एजेंडा जातिवादी, पूंजीवादी और राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के संकीर्ण विचारों का लागू करना है। भाजपा नीत सरकार धर्म के नाम पर हमेशा तनाव और नफरत का वातावरण पैदा करती है। दलित समाज और महिलाएं इस सरकार में कतई सुरक्षित नहीं हैं।"

बसपा सुप्रीमो ने कहा, 'भाजपा की गलत आर्थिक नीतियों के कारण गरीबी, बेरोजगारी और मंहगाई बढ़ रही है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से पेट्रोल/डीजल के दाम कम किए गए हैं, ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होते ही फिर तेजी से बढ़ेंगे।"

पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा, 'कांग्रेस, भाजपा सपा सबकी सरकारों में गरीबों, बेरोजगारों को पलायन करना पड़ा। इन सरकारों से निजात पाने के लिए बसपा की सत्ता में वापसी बहुत जरूरी है।"

उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार बनने परे कानून-व्यवस्था मजबूत की जाएगी, हर स्तर पर कानून का राज कायम किया जाएगा, धर्म के नाम पर किसी का शोषण/उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा।

सपा की सरकार बनने पर ब्राह्मणों पर लगे फर्जी मुकदमे वापस होंगेः अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया कि सपा की सरकार बनने पर काशी विश्वनाथ समेत अन्य मंदिरों के पुजारियों व पुरोहितों को मानदेय दिया जाएगा, संस्कृत शिक्षकों का सम्मान होगा और ब्राह्मणों सहित सभी पर लगे फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएंगे।

सपा मुख्यालय से मंगलवार को जारी बयान के अनुसार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से आज कई ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधियों ने भेंट किया और उन्हें अपने समर्थन का भरोसा दिलाया।

यादव ने उन्हें आश्वासन दिया कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर 'संस्कृत शिक्षकों का सम्मान होगा, मंदिरों का संरक्षण होगा, काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों सहित अन्य मंदिरों के पुजारियों को भी मानदेय दिया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि रामायण के कलाकारों को

भी मानदेय देंगे और फ्री श्रवण यात्रा शुरू होगी। उन्होंने सपा सरकार बनने पर ब्राह्मणों सहित सभी पर लगे फर्जी मुकदमे वापस लेने की भी घोषणा की।

गोरखपुर जिले के बाहुबली पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के पुत्र चिल्लूपार के विधायक और सपा उम्मीदवार विनय शंकर तिवारी के साथ ब्राह्मणों का प्रतिनिधिमंडल यहां सपा मुख्यालय में यादव से मिला।

बयान के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल में विप्र एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मित्रेश चतुर्वेदी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा (ब्रह्म समर्पित) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नानक चंद्र शर्मा, महामंत्री ब्राह्मण संघ हरीश शर्मा, ओम ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय द्विवेदी, ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष केपी शर्मा सहित कई प्रमुख लोग शामिल थे।

ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सपा प्रमुख को दिए गए अपने मांग पत्र में कहा है, 'भगवान परशुराम जयंती पर पूर्व में दिए गए सार्वजनिक अवकाश को पुनः बहाल किया जाए, ब्राह्मण आयोग का गठन हो तथा ब्राह्मण एवं ब्राह्मण हितों पर हो रहे कुठाराघात को रोका जाए।"

उसमें कहा गया है, 'केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों को दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न बंद किया जाए और खुशी दुबे को रिहा कर उस पर लगे झूठे मुकदमों को वापस लिया जाए।"

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2020 में कानपुर जिले के बिकरू गांव में एक गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर दुबे और उसके साथियों ने हमला कर आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी।

बाद में पुलिस ने विकास दुबे और उसके सहयोगी अमर दुबे समेत अन्य आरोपियों को अलग-अलग मुठभेड़ में मार गिराया। इस सिलसिले में पुलिस ने घटना से हफ्ते भर पहले ब्याह कर लाई गई अमर दुबे की नाबालिग पत्नी खुशी दुबे को भी गिरफ्तार किया है।

अखिलेश की सरकार बनेगी तो राम मंदिर और जल्दी तथा बेहतर बनेगाः रामगोपाल यादव

समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बारे में अपनी पार्टी के रुख के संबंध में गृह मंत्री अमित शाह के कथित बयानों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया कि अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो अयोध्या में ज्यादा बेहतर मंदिर का निर्माण होगा और जल्दी होगा।

उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए यादव ने कहा कि उनकी पार्टी भगवान राम के जन्मस्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण के खिलाफ नहीं है।

वह शाह के हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान दिए गए एक कथित बयान का संदर्भ दे रहे थे। बयान में शाह ने कहा था कि अखिलेश यादव अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण रोक नहीं पाएंगे।

रामगोपाल यादव ने कहा 'मंदिर का निर्माण कौन रोक रहा है? अगर अखिलेश सरकार सत्ता में आती है तो तेज गति से, ज्यादा बेहतर मंदिर का निर्माण किया जाएगा।"

सपा नेता ने राम मंदिर के निर्माण के लिए एकत्र किए जा रहे कोष में हेराफेरी का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि नीतियों के बारे में बात नहीं की जा रही है बल्कि अखिलेश यादव के खिलाफ असंसदीय भाषा का उपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने सवाल किया 'अगर आप अखिलेश के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करेंगे, उन्हें गुंडा कहेंगे तो क्या आपको वोट मिलेंगे ?"

यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभाजनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं और चुनाव जीतने के लिए वहां दंगे का माहौल बनाया जा रहा है।

भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 17 और उम्मीदवार घोषित किए, मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा

भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 17 उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन किया है जबकि विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वाति सिंह को इस बार मौका नहीं दिया है।

मंगलवार को भाजपा के घोषित उम्मीदवारों में लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वाति सिंह की जगह पार्टी ने राजराजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया है जो उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा (यूपीपीपीएस) से वर्ष 2007 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में प्रतिनियुक्ति पर गए थे और उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले ली।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सरोजनी नगर में स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह दोनों टिकट की दावेदारी कर रहे थे और इस टकराव को समाप्त करने के लिए पार्टी ने एक नया चेहरा मैदान में उतारा है।

भाजपा ने उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन को उनकी पुरानी सीट लखनऊ पूर्व से मौका दिया है जबकि 2017 में लखनऊ मध्य से चुनाव जीते कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को इस बार लखनऊ कैंट से उम्मीदवार बनाया गया है।

लखनऊ मध्य में पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रजनीश गुप्ता और लखनऊ पश्चिम में अंजनी

श्रीवास्तव भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र से योगेश शुक्ला को पार्टी ने मौका दिया है जबकि पिछली बार इस सीट पर भाजपा के ही अविनाश त्रिवेदी चुनाव जीते थे। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की विधायक पत्नी जय देवी को फिर से मलिहाबाद (अनुसूचित जाति) सीट से पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है।

उन्नाव जिले की भगवंतनगर सीट पर भाजपा ने आशुतोष शुक्ल को उम्मीदवार बनाया है जहां से 2017 में विधानसभा अध्यक्ष हृदय

नारायण दीक्षित चुनाव जीते थे। राज्यमंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को उनकी पुरानी सीट चित्रकूट से पार्टी ने टिकट दिया है।

इस सूची में रायबरेली की ऊंचाहार सीट से भाजपा संगठन के पदाधिकारी अमरपाल मौर्य, अमेठी के गौरीगंज से चंद्रप्रकाश मिश्रा मटियारी और फतेहपुर के जहानाबाद से राजेंद्र पटेल और सीतापुर से राकेश राठौर गुरू को मौका मिला है।

जहानाबाद क्षेत्र से पिछली बार राज्य मंत्री जयकुमार सिंह जैकी सहयोगी अपना दल (एस) से चुनाव जीते थे जिन्हें उनकी पार्टी ने इस बार फतेहपुर की बिन्दकी सीट से उम्मीदवार घोषित किया है।

उन्नाव, लखनऊ, फतेहपुर, रायबरेली और सीतापुर जिले में चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होना है।भाजपा उत्तर प्रदेश में अब तक 314 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है।

सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर की फाजिलनगर सीट से टिकट दिया

समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को तीन उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की। पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री रहे और हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर जिले की फाजिलनगर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है।

पार्टी ने कौशांबी की सिराथू सीट से पल्लवी पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, यहां पटेल का मुकाबला भाजपा नेता एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से होगा।

पार्टी ने सपा सरकार में मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा को लखनऊ की सरोजनीनगर सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। मिश्रा का मुकाबला भाजपा के राजेश्वर सिंह से होगा।

राजेश्वर सिंह को मंगलवार शाम भाजपा ने उम्मीदवार घोषित किया जो उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा (यूपीपीपीएस) से वर्ष 2007 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में प्रतिनियुक्ति पर गए थे और उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली।

कांग्रेस ने अखिलेश और शिवपाल के खिलाफ नहीं उतारे उम्मीदवार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा व प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे हैं।

इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं जबकि शिवपाल यादव इटावा जिले की जसवंतनगर सीट से चुनाव मैदान में हैं।

करहल और जसवंतनगर विधानसभा क्षेत्रों में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। दोनों क्षेत्रों में मंगलवार एक फरवरी को नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख थी।

कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह पारस्परिक सौहार्द है क्योंकि सपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था।

मैनपुरी से मिली सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव प्रकाश प्रधान ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्देश दिया था कि चूंकि सपा ने चुनाव में हमारे नेताओं के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़े किए थे, इसलिए पार्टी करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी।

प्रधान ने कहा कि पार्टी ने पहले ज्ञानवती यादव को इस सीट से उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन जब अखिलेश यादव ने यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो ज्ञानवती को नहीं उतारने का फैसला लिया गया।

अखिलेश यादव जहां पहली बार अपने पिता मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले करहल क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं शिवपाल सिंह यादव छठी बार जसवंतनगर सीट से चुनाव मैदान में हैं।

इटावा से मिली सूचना के अनुसार, जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से सपा-प्रसपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव छठवीं बार चुनाव मैदान मे हैं और उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है।

इटावा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मलखान सिंह ने बताया कि कांग्रेस की इटावा जिला इकाई ने जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए छह लोगों का नाम पैनल

को भेजा था किंतु पार्टी नेतृत्व ने वहां से किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया है।

अमरिंदर के हटने के बाद 42 विधायक मुझे पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थेः सुनील जाखड़

कांग्रेस की पंजाब इकाई के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने दावा किया है कि पिछले साल अमरिंदर सिंह को हटाए जाने के बाद 42 विधायक उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे।

जाखड़ ने अबोहर में मंगलवार को एक सभा को संबोधित किया था और इस सभा की ऑनलाइन सामने आई एक वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है। जाखड़ के भतीजे संदीप जाखड़ पंजाब विधानसभा चुनाव में अबोहर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं।

सुनील जाखड़ भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे। पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को तरजीह दी, जो अनुसूचित जाति समुदाय से पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने।

जाखड़ ने कहा, 'सुनील (जाखड़) को 42 वोट, सुखजिंदर रंधावा को 16, महारानी परनीत कौर (अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला की सांसद) को 12 वोट, नवजोत सिंह सिद्धू को छह वोट और (चरणजीत सिंह) चन्नी को दो वोट मिले थे।"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। जाखड़ ने कहा कि पार्टी ने उन विधायकों से जानना चाहा था कि वे अमरिंदर सिंह के जाने के बाद किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, '79 विधायकों को यह जानने के लिए बुलाया गया था कि वे किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सुनील विधायक भी नहीं थे।"कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सत्ता संघर्ष के बीच कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी के उस बयान के बाद जाखड़ के मुख्यमंत्री बनने की संभावना कम हो गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी को सिख चेहरे के साथ जाना चाहिए। पिछले साल अमरिंदर सिंह की जगह लेने वाले चरणजीत सिंह चन्नी अनुसूचित जाति समुदाय से पंजाब के पहले मुख्यमंत्री हैं।

कांग्रेस ने मेरे साथ धोखेबाजी कीः पार्टी नेता मोहिंदर सिंह कायपी

कांग्रेस की पंजाब इकाई के नेता मोहिंदर सिंह कायपी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि जालंधर के आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बदलने का आश्वासन देने के बाद भी उन्हें टिकट नहीं देकर उनकी पार्टी ने उनके साथ धोखेबाजी की है।

कांग्रेस ने 15 जनवरी को सुखविंदर कोटली को आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। कायपी टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं।

प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कायपी ने दावा किया कि पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश चौधरी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आदमपुर सीट पर उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाएगा।

उन्होंने दावा किया कि उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया कि मंगलवार को उन्हें कांग्रेस का अधिकृत पत्र सौंपा जाएगा ताकि वह अपना नामांकन पत्र दाखिल कर पाएं। आश्वासन मिलने पर वह अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जालंधर में निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंच गए।

कायपी ने दावा किया कि पार्टी ने आखिरी घड़ी में सुखविंदर कोटली को अधिकृत पत्र दे दिया। पूर्व सांसद ने कहा, 'पार्टी ने मेरे साथ धोखेबाजी की। वह मुझे नकार रही है।" उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही भावी कदम के बारे में फैसला करेंगे।

आप उम्मीदवारों ने दल बदल न करने का वादा करते हुए हलफनामे पर हस्ताक्षर किए

गोवा विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के सभी 40 उम्मीदवारों ने बुधवार को हलफनामे पर हस्ताक्षर किए और वादा किया कि वे भ्रष्टाचार या दल बदल में शामिल नहीं होंगे।

आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'गोवा की राजनीति के साथ सबसे बड़ी समस्या लगातार दल बदल की है। लोगों द्वारा हमारे उम्मीदवारों को वोट देने से पहले ही हम इस समस्या को खत्म कर देना चाहते हैं।" केजरीवाल के इस संबोधन के दौरान पार्टी के सभी 40 उम्मीदवार भी अपने हलफनामों के साथ मौजूद थे।

केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों ने हलफनामे के माध्यम से वचन दिया है कि वे किसी भी भ्रष्ट आचरण में शामिल नहीं होंगे और (निर्वाचित होने पर विधायक के रूप में) कार्यकाल के दौरान किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे।

उन्होंने कहा कि हलफनामा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप के किसी भी उम्मीदवार द्वारा इसका उल्लंघन करना कानूनी तौर पर विश्वास का उल्लंघन होगा। केजरीवाल ने कहा कि उम्मीदवार अपने हलफनामों की फोटोकॉपी राज्य के मतदाताओं के बीच बांटेंगे।

आप संयोजक ने कहा कि उनकी पार्टी गोवा में एक ईमानदार सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए दल बदल से इंकार करना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है।

केजरीवाल चुनावी राज्य गोवा के चार दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उनकी पार्टी सभी 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी।

गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होना है और मतगणना 10 मार्च को होगी।

भाजपा गोवा में अगली सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के दलबदल पर निर्भरः केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दावा किया कि गोवा विधानसभा चुनाव के बाद सत्तारूढ़ भाजपा की 'रणनीति" कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में लाकर सरकार बनाने की होगी।

पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने कहा, 'यह विधानसभा चुनाव गोवा के लिए महत्वपूर्ण है। गोवावासियों को यह तय करना है कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है। एक विकल्प आम आदमी पार्टी का समर्थन करना है, जिसने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने का वादा किया है। दूसरा विकल्प प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा का समर्थन करना है।"

केजरीवाल ने कहा, 'पिछले चुनाव में गोवा के लोगों ने बीजेपी सरकार से तंग आकर कांग्रेस को चुना था। लेकिन कांग्रेस विधायकों ने उन्हें निराश किया।"

केजरीवाल ने कहा कि राज्य के हर हिस्से में कांग्रेस के दलबदल की चर्चा के साथ इस बार भी यही स्थिति थी। उन्होंने दावा किया, 'भाजपा ने एक नयी रणनीति बनाई है। कांग्रेस उम्मीदवार अपनी सीट जीत गए, तो वे भाजपा में शामिल हो जाएंगे।"

साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वह सरकार नहीं बना सकी। इसके अधिकांश विधायकों ने अगले पांच वर्षों में पार्टी छोड़ दी।

क्या टॉप ब्रांडों के शहद में मिलावट है? जर्मन लैब की जांच रिपोर्ट में दावा

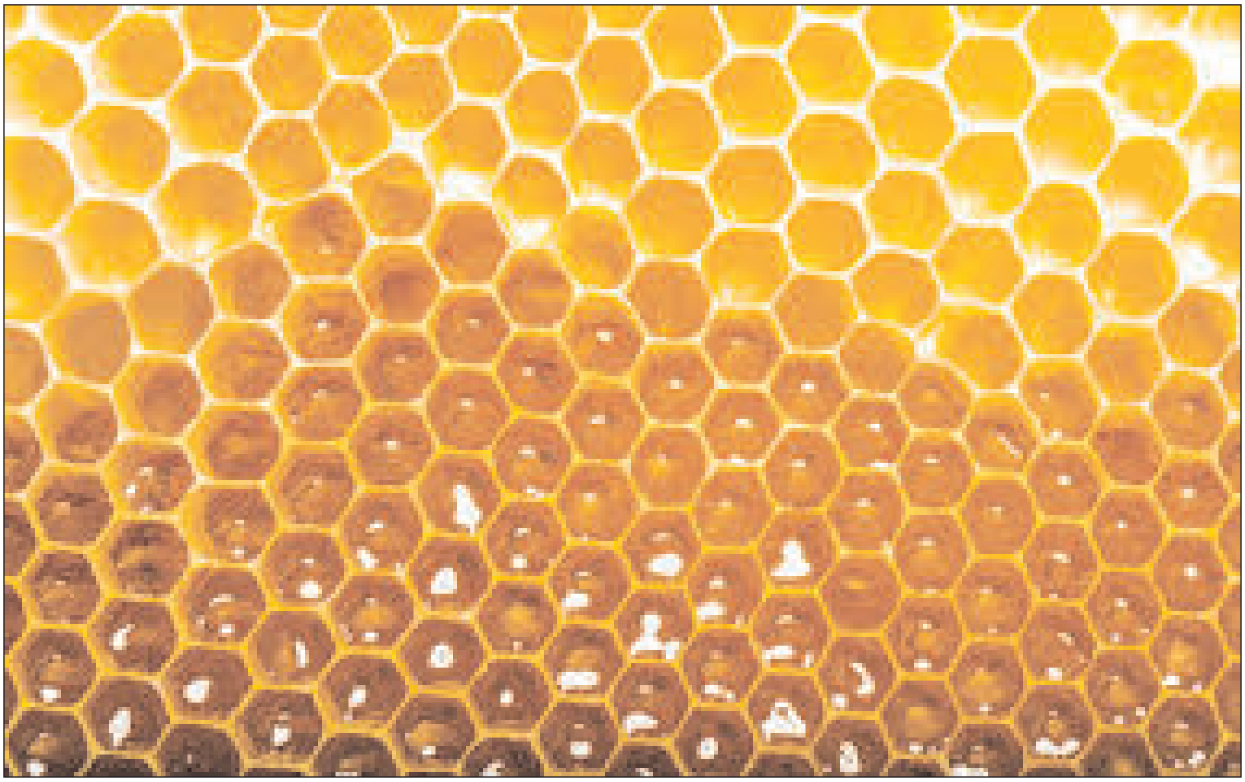

देश के टॉप शहद ब्रांडों में से अधिकतर जर्मन लैब में हुए गुणवत्ता परीक्षण के टेस्ट में फेल हो गए हैं। कुल 22 ब्रांडों में से सिर्फ 5 ब्रांड यानी 23 फीसदी ब्रांड ही मानक टेस्ट में पास हो पाए हैं। मानक परीक्षण में फेल होने वाले ब्रांडों में पतंजलि, डाबर, झंडू, हिमालया, हितकारी और वैद्यनाथ जैसे शीर्ष ब्रांड शामिल हैं। मानक परीक्षण पास करने वाले ब्रांडों में सफोला, मार्कफेड सोहना और नेचर्स नेक्टर शामिल हैं।

लैब और जांच दोनों की साख है

शहद में मिलावट की जांच सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) और डाउन टू अर्थ ने करवाई थी। इस जांच का महत्त्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इन ब्रांडों के शहद में मिलावट का स्तर जांचने में भारतीय लैब्स नाकाम रही थीं। सीएसई की डायरेक्टर सुनीता नारायण ने बताया कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम के एडवांस्ड लैब टेस्ट को जर्मनी में कराया गया है। सीएसई के मुताबिक, मधुमक्खियों से मिलने वाले शहद को चावल, मक्का, चुकंदर और गन्ने से बनने वाले शुगर सिरप के साथ मिलाकर उसे शुद्ध शहद के नाम पर बेचा जा रहा है। ये सस्ता शुगर सिरप चीन से आयात किया जाता है। किसी भी शहद को शुद्ध शहद तभी कहा जा सकता है जब वो इसके गुणवत्ता के परीक्षण के लिए निर्धारित 18 परीक्षणों को पास कर सके।

शीर्ष ब्रांडों ने जांच को खारिज किया

जांच के नतीजों को लेकर शीर्ष ब्रांडों ने सवाल उठाए हैं। कई ब्रांडों ने मिलावट के दावों को खारिज कर दिया है। पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने इसे देश की शहद इंडस्ट्री की छवि" खराब करने की कोशिश बताया है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि, सीएसई की रिपोर्ट जर्मन तकनीक को बढ़ावा देने की एक चाल लगती है।

डाबर के प्रवक्ता ने कहा कि ये ब्रांड का नाम खराब करने की कोशिश है। डाबर के प्रवक्ता ने एक वेबसाइट से बातचीत में स्पष्ट किया कि उनका शहद 100 प्रतिशत शुद्ध है और ये पूर्ण रूप से स्वदेशी भी है। इसमें कोई शुगर या मिलावट नहीं की जाती। प्रवक्ता ने कहा कि शहद या सिरप चीन से आयात नहीं किया जाता और इसे पूरी तरह भारतीय मधुमक्खी पालकों से ही लिया जाता है। डाबर ने जांच रिपोर्ट को दुर्भावना से प्रेरित और ब्रांड की छवि खराब करने की कोशिश बताया।

झंडू ब्रांड के तहत शहद बेचने वाली इमामी ने कहा कि उसका शहद सभी गुणवत्ता नियमों का पालन करता है। इमामी ने कहा, एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते हम भारत सरकार और भारतीय खाद्य संरक्षा प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई से निर्धारित प्रोटोकॉल और नियमों का पालन करते हैं।

भारत सबसे बड़ा घूसखोर देश, एक साल में भ्रष्टाचार और बढ़ा : सर्वे

घूसखोरी में भारत का कोई तोड़ नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस बारे में एक सर्वेक्षण कराया। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में पाया गया कि एशियाई देशों में भारत सबसे बड़ा घूसखोर देश है।

सर्वेक्षण में ये जानने का प्रयास भी किया गया कि पिछले एक साल में देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है या कम हुआ है। जुलाई से सितंबर के बीच इसी साल कराए गए इस स्र्वेक्षण में 17 देशों के 20000 लोग शामिल हुए।

एक खास बात जो सर्वेक्षण में सामने आई वो ये कि भारत में घूसखोरी की आदत सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में है। भारत में 39 फीसदी लोगों का कहना था कि उन्हें सरकारी सुविधओं का इस्तेमाल करने के लिए घूस देनी पड़ी। चीन में ये दर 28 फीसदी, नेपाल में 12 प्रतिशत, बांगलादेश में 24 और जापान में महज 2 प्रतिशत रही।

पुलिस सबसे भ्रष्ट

जिन सरकारी सुविधाओं के बारे में सर्वेक्षण में पूछा गया उनमें पुलिस, अदालतें, सरकारी अस्पताल और बिजली - पानी जैसी दूसरी बुनियादी सुविधाओं को शामिल किया था। इन सबमें सबसे ज्यादा घूसखोरी की शिकायत पुलिस के खिलाफ थी। करीब 42 प्रतिशत लोगों ने माना कि उन्हें पुलिस को रिश्वत देनी पड़ी। पहचान पत्र और दूसरे सरकारी कागजातो के लिए भी 41 प्रतिशत लोगों को घूस देनी पड़ी तब जाकर उनका काम हुआ।

भारत में काम कराने के लिए निजी परिचय का फायदा उठाने और जोर -जुगाड़ लगाने का काम भी खूब होता है। पुलिस, अदालतों और बुनियादी सुविधाओं के लिए करीब 46 प्रतिशत लोगों ने अपने संपर्कों का फायदा उठाया। चीन में ये दर 32 और जापान में सबसे कम यानी सिर्फ 4 प्रतिशत है। इन आंकडों से जाहिर होता है कि भारत में ये सुविधाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं और सरकारी मशीनरी उसका खूब बेजा फायदा उठा रही है।

चुनावी भ्रष्टाचार के मामले में दक्षिण-पूर्व एशियाई देश कहीं आगे हैं। थाईलैंड और फिलीपींस के करीब 28 फीसदी वोटरों ने माना कि उन्होंने पैसे लेकर वोट दिए जबकि इंडोनेशिया में ये दर 26 प्रतिशत रही। भारत इस मामले में चौथे नंबर पर रहा। यहां 18 प्रतिशत लोगों ने माना कि उन्होंने पैसे लेकर वोट दिया।

सरकारी अफसरों द्वारा काम करने के बदले लड़कियों की मांग करने के मामले में भी भारत चौथे नंबर का देश है। यहां 11 फसीदी लोगों ने माना कि उनसे काम कराने के एवज में लड़कियों की मांग की गई थी। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा 18 प्रतिशत ऐसे मामले सामने आए जबकि श्रीलंका में 17 और थाईलैंड में 15 प्रतिशत लोगों से काम के बदले सेक्स की मांग की गई।

जहां तक पिछले 12 महीनों मे भ्रष्टाचार की स्थिति की बात है, भारत में 47 प्रतिशत लोग मानते हैं कि इस दौरान देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। वहीं 63 फीसदी ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लडाई में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। ये भी ध्यान देने की बात है कि भारत में 51 प्रतिशत लोगों का सरकार पर या तो एकदम भरोसा नहीं है या बहुत कम यकीन है। यहीं नहीं भारत में 63 प्रतिशत लोगों का मानना है कि भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं और उन्होंने उसके खिलाफ मुंह खोला तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

भारत सरकार ने कहा, देश में जीवंत लोकतंत्र, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट भ्रामक

भारत सरकार ने फ्रीडम हाउस की तरफ से जारी रिपोर्ट में भारत के बारे में जो कुछ भी निष्कर्ष प्रकाशित किए गए हैं उसे भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी एक बयान में स्पष्ट किया गया है कि भारत में शासन एक संघीय व्यवस्था के तहत चलाय़ा जाता है। राज्यों में अलग-अलग पार्टियां शासन करती है। ये पार्टियां चुनावी प्रक्रिया के तहत चुन कर आती हैं, जिसे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोग संपन्न कराता है। ये सब एक जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण हैं।

सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में सिलसिलेवार 7 बिंदुओं में फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में उठाए गए सवालों के जवाब दिए गए।

भारत में मुस्लिमों के खिलाफ पक्षपातः बयान में कहा गया है कि संविधान के मुताबिक, भारत सरकार देश के सभी नागरिकों को समान मानती है और सभी नियम-कानून बिना किसी भेदभाव के देश के हर नागरिक पर लागू होते हैं। दिल्ली दंगों में प्रशासनिक मशीनरी ने तेजी के साथ बिना किसी पक्षपात के काम किया।

राजद्रोह कानून :

विज्ञप्ति में कहा गया कि पब्लिक ऑर्डर और पुलिस दोनों ही राज्य सरकार के विषय क्षेत्र हैं। नियम-कानून को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

प्रवासियों का पलायन :

विज्ञप्ति के अनुसार लॉकडाउन का फैसला केंद्र और राज्य के स्तर पर लिया गया। एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर भारी संख्या में लोग आते-जाते तो संक्रमण फैलता। लोगों को लॉकडाउन की वजह से परेशानी न हो इसलिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए।

मानवाधिकार की रक्षा के लिए नियम :

विज्ञप्ति मेंकहा गया है कि भारत के संविधान में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कई नियम-कानून हैं। मानवाधिकार संरक्षण कानून 1993 भी उनमें से एक है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य

मानवाधिकार आयोगों का गठन किया गया है। यहां मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए काम किया जाता है।

मीडिया पर दबाव नहीं :

विज्ञप्ति में लिखा गया है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी है। भारत सरकार पत्रकारों सहित देश के सभी निवासियों की सुरक्षा को सबसे अधिक अहमियत देती है। भारत सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक एडवाइज़री जारी की है।

इंटरनेट सेवाओं पर रोक :

इंटरनेट समेत दूरसंचार सेवाओं पर रोक, टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज (पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी) रूल्स, 2017 के प्रावधानों के तहत होती हैं जिसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव की मंजूरी की जरूरत पड़ती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है।

एमनेस्ट्री इंटरनेशनल के बारे में स्पष्टीकरण :

एमनेस्टी इंटरनेशनल को एफसीआरए अधिनियम के तहत केवल एक बार 20 साल पहले अनुमति मिली थी। उसके बाद से उसे भारत की सरकारों से कोई मंजूरी नहीं मिली। एमनेस्टी को बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के विदेश से पैसा भेजा गया जो नियमों के विरुद्ध था।

क्या था फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में ?

अमेरिकी शोध संस्थान फ्रीडम हाउस ने भारत में अधिकारों और आजादी जैसे विषयों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र देशों की श्रेणी में रख दिया था। पूर्ण स्वतंत्र देशों के लिए निर्धारित 100 अंकों में से भारत के अंक घटकर 67 हो गए हैं। पहले ये अंक 71 थे। 211 देशों की इस सूची में अब भारत का स्थान 88 हो गया है पहले ये 83 था। संस्थान की ताजा रिपोर्ट में इसके लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को कठघरे में खड़ा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही देश में राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता में कमी आई है। संस्था का आंकलन है कि भारत में मानवाधिकार संगठनों पर दबाव बढ़ा है। बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को डराने और उनके खिलाफ मामले दर्ज कर उन पर दबाव बनाने का चलन बढ़ा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हुए कई घटनाएं हुई हैं। फ्रीडम हाउस एक अमेरिकी शोध संस्थान है जो हर साल 'फ्रीडम इन द वर्ल्ड" रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट में दुनिया के अलग-अलग देशों में राजनीतिक आजादी और नागरिक अधिकारों के स्तर की समीक्षा की जाती है।

गजबै है बिहार, राज्य में सुरक्षा का बंटाधार, वीआईपी की भरमार

देश में पुलिस सुरक्षा सोशल स्टेटस का सिंबल है या वास्तव मे उसका बड़ा ताल्लुक वीआईपी सुरक्षा से है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डवलपमेंट के हालिया आंकडों को देखें तो चौंकाने वाली बातें निकल कर सामने आई हैं। बिहार में तो गजब ही हालत है वहां साल 2018 में करीब 4600 वीआईपी थे जो देश में सबसे ज्यादा थे। 2019 में इस संख्या में 50 फीसदी की कटौती कर दी गई तब जाकर वहां 2300 लोगों को वीआईपी सुरक्षा मुह्य्या कराई गई है। इस काम में राज्य के हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस बारे में एक रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया गया है कि बंगाल, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा पुलिसकर्मियों को वीआईपी सुरक्षा के काम में लगाया गया है जबकि आतंकवाद और हिंसा प्रभावित राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों में वीआईपी सुरक्षा के नाम पर बहुत ही कम पुलिसकर्मियों की तैनाती है।

ब्यूरो ने साल 2019 के आंकडों को जारी करते हुए बताया है कि, 66000 पुलिसकर्मी 19000 लोगों की सुरक्षा में लगाए गए हैं। इन लोगें में मंत्री, सांसद, विधायक, जज और अफसर शामिल हैं। ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा करीब 3000 लोगों को पुलिस सुरक्षा दी गई है जबकि पंजाब में ये आंकड़ा 2500 लोगों का है। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ राज्य में सिर्फ 315 लोगों को पुलिस सुरक्षा मुहय्या कराई गई है।

दिल्ली में सिर्फ 501 लोगों को वीआईपी सिक्योरिटी दी गई है लेकिन यहां इस काम में 8 हजार से ज्यादा पुलसिकर्मी लगाए गए हैं जो देश में सबसे ज्यादा हैं।

बंगाल में वीआईपी बढ़े

ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में साल 2019 में कुल 3142 लोगों को वीआईपी सुरक्षा उपलब्ध कराई गई जो पिछले

साल के मुकाबले करीब 13 प्रतिशत ज्यादा है। राज्य मे वीआईपी सुरक्षा के काम में कुल 6000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया। पंजाब में 2600 लोगों को वीआईपी सुरक्षा दी गई और करीब 7700 पुलिसकर्मियों को इस काम में लगाया गया। बिहार में कुल 2300 लोगों को वीआईपी सुरक्षा दी गई। आश्चर्य की बात ये है कि बिहार में ये आंकड़ा तब है जबकि वहां साल 2018 के मुकाबले वीआईपी सुरक्षा दिए जाने के के मामलों में करीब 50 फीसदी की कटौती कर दी गई थी। साल 2018 में बिहार में वीआईपी सुरक्षा के दायरे मं कुल 4600 वीआईपी आते थे।

यहां ध्यान देने योग्य बात ये है कि, साल 2018 के मुकाबले वीआईपी सुरक्षा हासिल करने वाले लोग की संख्या में कमी की गई है और साल 2018 के 21300 मामालों के मुकाबले 2019 में ये संख्या घटकर 19467 हो गई है। वहीं, इस दौरान वीआईपी सरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या घटने के बजाए बढ़ गई है। पहले कुल 63061 पुलिसकर्मी वीआईपी सुरक्षा में लगे थे जो साल 2019 में बढ़कर 66043 हो गए। इसका सीधा सा मतलब है कि वीआईपी सुरक्षा का स्तर बढ़ाया गया है।

हिंसा प्रभावित राज्यों में वीआईपी कम

आश्चर्यजनक रूप से जम्मू-कश्मीर, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ जैसे आतंकवाद और हिंसा प्रभावित राज्यों में वीआईपी सुरक्षा के मामले काफी कम हैं। जम्मू-कश्मीर में साल 2019 में कुल 1184 लोगों को वीआईपी सुरक्षा उपलब्ध कराई गई और इस काम में कुल 3000 पुलिस कर्मियों को लगाया गया। असम में 1199 लोगों को वीआईपी सुरक्षा दी गई और 4000 पुलिसकर्मियों को इस काम में लगाया गया।

मणिपुर में 200 वीआईपी के लिए करीब 2000 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया जबकि छत्तीसगढ़ में 315 वीआईपी के लिए कुल 2700 पुलिसकर्मियों को वीआईपी सुरक्षा में तैनात किया गया। जिन राज्यों में सबसे कम वीआईपी सुरक्षा के मामले रहे उनमें गोवा में 32, उड़ीसा में 48 और केरल में सिर्फ 57 मामले थे।

क्यों जरूरी हैं भारत के लिए ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधन?

भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत वाला देश है। उसकी गिनती अमेरिका, रूस और चीन के बाद होती है। हालांकि प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के लिहाज से भारत दुनिया के तमाम विकसित देशों के मुकाबले काफी पीछे है। अमेरिकी एनर्जी इनफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया से तेल आयात पर निर्भर करता है और देश में उसके पास खुद के 5.5 अरब बैरल तेल का भंडार है। कोयले को ऊर्जा का प्रमुख स्त्रोत बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दुनिया का पांचवां सबसे ज्यादा कोयले का भंडार है। देखा जाए तो भारत दुनिया के तमाम दूसरे विकासशील देशों की तरह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खासतौर से ऊर्जा के पारंपरिक संसाधनों पर ही निर्भर कर रहा है। लेकिन समय के साथ ऊर्जा के पारंपरिक संसाधनों का क्षरण होता जा रहा है और जल्दी ही वे खत्म हो जाएंगे। इस दृष्टि से दुनिया के लगभग सभी देश ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों की तरफ निगाह दौड़ा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा जोर अक्षय ऊर्जा और हरित ऊर्जा के संसाधानों पर हैं। इन संसाधनों से पैदा हुई ऊर्जा सस्ती तो होगी ही साथ ही वह पर्यावरण और पृथ्वी की सुरक्षा की दृष्टि से भी कारगर होगी।

किसी भी देश के विकास का इंजन ऊर्जा को माना जा सकता है। किसी देश में प्रति व्यक्ति होने वाली ऊर्जा की खपत वहां के जीवन स्तर का भी सूचक है। यही नहीं, आर्थिक विकास का भी ऊर्जा उपयोग के साथ गहरा संबंध होता है। इसलिए भारत जैसी तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। इन्हीं पहलुओं के मद्देनज़र एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल उत्पादक देशों से ऊर्जा की लागत को कम करने का आग्रह किया ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को मदद मिल सके। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक में वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से 40 फीसदी बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

इसमें दो राय नहीं कि तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के भरण-पोषण और सुख-सुविधाओं के लिए संसाधनों की तेज़ी से खपत हो रही है। लेकिन इससे पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं का जन्म हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि बढ़ती जनसंख्या और ऊर्जा आपूर्ति के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए? सवाल यह भी है कि पर्यावण और भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर भारत की आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। साथ ही वर्तमान में भारत की किन स्रोतों पर कितनी निर्भरता है और इसे कैसे बदला जा सकता है?

भारत में पारंपरिक ऊर्जा पर भारी निर्भरता

भारत अभी भी अपनी कुल ऊर्जा क्षमता का 40 प्रतिशत परम्परागत ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है। सरकार ने 1950 में एक कार्यक्रम शुरू किया था। इसके अन्तर्गत जैव ऊर्जा संयन्त्रों का निर्माण किया जाता था और लोगों को उनके बारे में बताया जाता था। सौर कुकर विकसित करने पर भी कुछ अनुसंधान किया गया लेकिन नए अक्षय ऊर्जा के स्रोत विकसित करने की दिशा में गम्भीर प्रयास 1973-74 में तेल के मूल्यों में भारी बढ़ोत्तरी के बाद किए गए। यह कार्यक्रम पहले भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत शुरू किया गया और फिर उसे एक नए विभाग गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग के अन्तर्गत लाया गया। 1990 में इस विभाग को पूर्ण पृथक मन्त्रालय में बदल दिया गया।

जैव ईंधन के प्रयोग का एक प्रमुख दुष्परिणाम वातावरण पर उसका हानिकारक प्रभाव है। वह दुष्परिणाम विश्व और स्थानीय दोनों स्तरों पर हो रहा है। 1992 के रियो शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के समझौते की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें स्पष्ट रूप से धरती का तापमान बढ़ाने वाली ग्रीन हाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन-डाई-ऑक्साइड का इस्तेमाल घटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

अक्षय ऊर्जा है बेहतर विकल्प

गौर करने वाली बात है कि पिछले 150 से 200 वर्षों में मनुष्य ने ऊर्जा ज़रुरतों को पूरा करने के लिए पृथ्वी की सतह के नीचे दबे संसाधनों पर भरोसा किया है। लेकिन अब व\ आ गया है कि सुरक्षित भविष्य के लिये सौर और पवन ऊर्जा जैसे उपलब्ध संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। इसके लिए एक मज़बूत नीतिगत ढांचे की आवश्यकता होगी जिसमें भारत अहम् भूमिका निभा सकता है। इसके लिये भारत संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के मंच पर ले जाना चाहता है जिससे ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी देशों का ध्यान अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर खींचा जा सके।

अक्षय ऊर्जा क्या है ?

अक्षय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो प्रदूषण का कारण नहीं बनती, तथा जिनके स्त्रोतों का क्षय नहीं होता या फिर जिनके स्रोतों का फिर से इस्तेमाल होता रहा है। पवन ऊर्जा, जलविद्युत ऊर्जा, ज्वारभाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोमास और सौर ऊर्जा आदि अक्षय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं।

अक्षय ऊर्जा में भारत की स्थिति ?

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित हमारे योगदानों और एक स्वच्छ ग्रह के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए भारत ने संकल्प लिया है कि 2030 तक बिजली उत्पादन की हमारी 40 फीसदी स्थापित क्षमता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, बायो-पावर से 10 गीगावाट और छोटी पनबिजली परियोजनाओं से 5 गीगावाट क्षमता शामिल है।

इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही भारत विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकों की जमात में शामिल हो जाएगा। यहां तक कि वह कई विकसित देशों से भी आगे निकल जाएगा। फिलहाल 2018 में देश की कुल स्थापित क्षमता में तापीय ऊर्जा की 63.84 फीसदी, नाभिकीय ऊर्जा की 1.95 फीसदी, पनबिजली की 13.09 फीसदी और नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 21.12 फीसदी है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। अब तक 71 देशों ने इस गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इनमें से 48 देशों ने इसे मंज़ूरी दे दी है। इस गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता को ख़त्म कर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, सभी सदस्य देशों को सस्ती दरों पर सोलर तकनीक उपलब्ध कराना और इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना आदि भी इसके उद्देश्यों में शामिल है।

दौसा की रूबी पारीक कैसे बन गई जैविक किसानी की मिसाल

राजस्थान के दौसा जिले की एक महिला किसान रूबी पारीक ने 13 साल की अथक मेहनत के बलबूते पर देश में एक सफल जैविक किसान के तौर अपनी पहचान बनाने में कामयाबी पाई है। रूबी पारीक बताती है कि साल 2004 में उनकी शादी दौसा जिले में खटवा गांव के रहने वाले ओम प्रकाश पारीक से हुई तब उन्हें खेती के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन उनके ससुराल में जीविका का मुख्य साधन खेती था । धीरे-धीरे उन्होंने भी खेती के कार्य में हाथ बंटाना शुरू कर दिया ताकि उनके परिवार की मदद हो सके। रूबी का कहना है कि, खेती के कार्य के दौरान उनकी रुचि खेती में बढ़ती गई और उन्होंने खेती किसानी में नई –नई जानकारियां भी हासिल की। इस कार्य में उनके पति ने भी भरपूर सहयोग किया।

पति का मिला साथ तो खेती में किया कमाल

रुबी पारिक खेती के बारे में जानकरियां जुटाने के लिए कृषि बैठकों में शामिल होती थी। इसी दौरान साल 2008 में रुबी के गांव मे कृषि विज्ञान केन्द्र में कृषि वैज्ञानिक आए और उन्होने किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया। कृषि विज्ञान केन्द्र की तरफ से गांव के किसान, विशेषकर महिला किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। रूबी को भी उनके पति ओम प्रकाश ने इस ट्रेनिंग में जाने के लिए प्रेरित किया। तीन दिन की ट्रेनिंग में रूबी ने जैविक खेती के बारे बहुत कुछ जाना और समझा। वहां रसायनों, उर्वरको और कीटनाशकों से होने वाले दुष्प्रभाव और बीमारियों के बारे में उनकी जानकारी सबसे ज्यादा बढ़ी। उन्होंने तय किया कि वे ना सिर्फ खुद जैविक खेती अपनाएंगी बल्कि अपने आस-पास के किसानों को भी जैविक खेती करने के लिए समझाएंगी।

जैविक खेती का उठाया बीड़ा

साल 2008 में रूबी पारीक ने अपने खेतों

में जैविक तरीके से खेती शुरू कर दी। पहले पहल तो उन्हें अपेक्षाकृत नतीजे नहीं मिले लेकिन दूसरे-तीसरे साल से उपज की गुणवत्ता के साथ-साथ पैदावार भी काफी बढ़ने लगी। अभी रूबी ने 20 बीघा ज़मीन पर सभी तरह की फसलें जैसे कि बाजरा, गेंहूँ, चना, ग्वार, मूंगफली, और जौ को जैविक तरीके से उगाती हैं। रुबी ने शुरू में जैविक तरीके से कुछ साग-सब्जियां ही उगाईं। इसके लिए उन्होंने केवीके में खाद बनाना और कुछ जैविक पेस्टिसाइड बनाना सीखा था। फिर उन्होंने अपने खेतों में इस्तेमाल करने के लिए खुद ही जैविक खाद और जैविक पेस्टीसाइड बनाना शुरू किया । इसके अलावा, केवीके ने उनके गाँव में एक किसान क्लब का गठन भी किया जिसका मकसद था कि गांव के किसान साथ में बैठकर जैविक खेती सम्बन्धी विषयों पर चर्चा और परिचर्चा करें और एक-दूसरे की मदद करें । रूबी को जैविक खेती में ज्यादा सक्रिय होकर काम करने के चलते उन्हें किसान क्लब की अध्यक्ष बना दिया गया।

बडे.पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट और अजोला उत्पादन

रूबी ने अपने गाँव में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने पति के साथ मिलकर एक 200 मीट्रिक टन की एक कम्पोस्ट यूनिट शुरू की है । यहाँ पर वर्मीकम्पोस्ट खाद बनाने के साथ-साथ केंचुआ-पालन का काम भी किया जाता है । रुबी के इस यूनिट की वजह से पूरे दौसा में जैविक खेती करने वाले किसानों को वर्मी कम्पोस्ट उपलब्ध हो जाता है। इस वर्मीकम्पोस्ट यूनिट को शुरू करने में उन्हें नाबार्ड से काफी मदद मिली। रुबी का कहना हैं कि इस यूनिट को शुरू करने का उद्देश्य अपनी खेती को पूरी तरह जैविक करने के साथ-साथ अपने इलाके के दूसरे किसानों को भी जैविक खेती से जोड़ना था।वर्मीकम्पोस्ट यूनिट के अलावा रूबी ने अपने यहा अजोला उत्पादन इकाई की स्थापना की है। अज़ोला एक तरह की फ़र्न है और गुणवत्ता से भरपूर अजोला को पशुओं के चारे के रूप मे इस्तेमाल किया जाता है। रूबी कहती हैं कि अज़ोला उत्पादन की लागत, सामान्य हरे चारे के लिए इस्तेमाल होने वाली चारे फसलों से काफी कम है और इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। इसे सूखे चारे में मिलाकर पशुओं को दिया जाता है। पशुओं को अज़ोला खिलाने से उनकी शारीरिक वृद्धि और उनके उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में भी अच्छी वृद्धि होती है। इसके अलावा, अज़ोला को फसलों में एक जैविक खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

सरकार और समाज से मिला सम्मान

जैविक कृषि में योगदान के लिए रूबी पारीक को भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से पुरस्कार और सम्मान से भी नावाजा गया। वे कहती है कि जब गांव में इतना बड़ा सम्मान मुझे मिला तो इसके साथ आई ज़िम्मेदारी का एहसास भी उन्हें पूरा-पूरा था। उन्होंने पूरी ईमानदारी से इस ज़िम्मेदारी को निभाने का निर्णय उसी वक्त कर लिया था वो कहती हैं कि उन्हें ख़ुशी है कि वो इस ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभा पा रही हैं। इस तरह जैविक खेती और कारोबार दोनों में अपनी ख़ास सोच, मेहनत और लगन के कारण सफल हुई रूबी एक स्वस्थ समाज और देश के निर्माण के लिए प्रयासरत है क्योंकि उन्होंने खेती जैसे क्षेत्र में,महिलाओं के लिए भी संभावनाओं के नए दरवाज़े खोल दिए हैं।

शिक्षा के बुनियादी ढांचे में बदलाव की जरूरत

देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई तरह की चुनौतियां समाने आ रही हैं। शिक्षा की गुणवत्ता से लेकर बुनियादी शैक्षिक ढांचे के प्रश्न देश और समाज के सामने हैं। शिक्षा के क्षेत्रीय स्वरूप और उसे राष्ट्रीय मूल्यों में पिरोने की चुनौती सबसे बड़ी है। शहरों में अच्छी शिक्षा की बात होती है तो गांवों में बात शिक्षा की उपलब्धता की है। देश के सामने मौजूद ब्रेन ड्रेन की सम□भी एक अहम मसला है। सवाल तमाम हैं। ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका के संपादक विनोद आशीष ने इन सवालों के जवाब मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के विभिन्न मौकों पर दिए गए वक्तव्यों में तलाशने का प्रयास किया है। पाठकों को सामने वैचारिक स्पष्टता के लिए उसे सवाल जवाब का रूप दिया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में आप किस तरह के बुनियादी बदलाव की जरूरत महसूस कर रहे हैं ?

देश में शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर शिक्षा तक बदलाव की आवश्कता है। हमने नई शिक्षा नीति की पूरी तैयारी कर ली है। इसे लागू कैसे किया जाएगा सरकार में इन दिनों इस पर मंथन चल रहा है। अगले 2-3 महीनों में देश के सामने मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति होगी। नई शिक्षा नीति से देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति न सिर्फ प्राइवेट स्कूलों जैसी होगी बल्कि देशभर में लोग सरकारी स्कूलों में दाखिले को पहली

प्राथमिकता देंगे।

हमारा दूसरी बड़ी चिंता शिक्षकों की गुणवत्ता को लेकर हैं। ऐसा महसूस होता है कि हमारे देश में शिखक को न सिर्फ पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए बल्कि उसकी भूमिका एक प्रेरक के रूप में कहीं ज्यादा होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके। उसके सामने उसका शिक्षक ही उसके सवालों का जवाब हो।

हमारी एक और चिंता संसाधानों को लेकर है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे हमारा जोर उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर ज्यादा है।

महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना हमारी प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि महिला को शिक्षित करने से ही बड़े बदलाव की बुनियाद रखी जा सकती है।

संक्षेप में कहें तो हम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं जिससे शिक्षा न सिर्फ ज्ञान का माध्यम बन सके बल्कि उससे रोजगार, उद्यमशीलता और आत्म निर्भरता की सोच को भी विकसित किया जा के।

अगर शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकताओं की बात की जाए तो किन बातों को सामने रखा जाएगा?

हमारी सबसे बड़ी कोशिश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वयवस्था के विकास की है। हमने कई कदम उठाए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि देश के बेस्ट ब्रेन का पलायन रोकने के लिए विश्व स्तरीय शोध की सुविधाएं देश में मुहय्या कराई जाएं। केन्द्र सरकार ने देश के सभी आईआईएम को पूरी स्वायत्तता देने के साथ शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार का अगाज किया है। सरकार अब यूजीसी में सुधार प्रक्रिया शुरू कर रही है। भारत ने ओपन लर्निंग की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अगले कुछ दिनों में उत्कृष्ट शिक्षा के लिए डिजिटल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। यह डिजिटल सॉल्यूशन 'सबको शिक्षा' और 'अच्छी शिक्षा' के लिए बेहद अहम होगा।

अगर प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की बात की जाए तो सरकार के एजेंडे में ये विषय कहां खड़े हैं ?

आपकी जानकारी में होगा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जब बजट पेश किया था तो उसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एलान किया

गया है। सरकार के इस एलान से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, प्रवेश परीक्षाएं कराने की एजेंसी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए स्कूलों के लिए एक साथ प्रवेश परीक्षाएं होंगी। एंट्री और एक्जिट परीक्षाएं एक जगह होंगी। लेकिन, बोर्ड परीक्षाएं पहले जैसी ही होंगी। इस तरह की एजेंसी दुनिया में कई जगह हैं। सरकार की ओर से छात्रों के जीवन में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है और सरकार प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारेगी।

दरअसल ये व्यवस्था सीखने के स्तर को परिभाषित करती है जिसे किसी छात्र से किसी खास कक्षा में अपेक्षा की जाती है। अकादमिक सत्र 2017-18 से पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के छात्रों के सीखने के स्तर से जुड़े विशेष मानकों को नियमों में शामिल किया जाएगा और उसे लागू किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अस्तित्व में है और उसमें लर्निंग आउटकम का जिक्र है लेकिन उसे परिभाषित नहीं किया गया है। हमारा मंत्रालय शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दे रहा है और बीएड आदि कराने के सिलसिले में गुणवत्ता का अभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यापन शिक्षक का मुख्य कार्य है। जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें सरकारी स्कूलों में कक्षाएं लेनी होगी। उनका मूल्यांकन न सिर्फ निगरानी करने वाले शिक्षक बल्कि छात्रों से प्राप्त प्रतिक्रिया पर भी होगा। यह एक बड़ा बदलाव है जो हम करने जा रहे हैं।

जहां तक माध्यमिक स्तर पर बदलाव की बात है हमारा जोर इस बात पर है कि बच्चे शिक्षा को बीच में न छोड़ें। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के नामांकन प्रतिशत में बहुम कम अंतर रह गया है और यह बेहतर होकर 48 से 49 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है। ऐसी स्थिति पहले थी जब स्कूलों में लड़कियों का नामांकन का स्तर कम था। लेकिन पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरु किए गए सर्व शिक्षा अभियान के परिणाम स्वरुप पिछले कई वर्षों में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान का मकसद सर्वसुलभ नामांकन और लड़कियों सहित सभी बच्चों को स्कूल में लाए जाने के लिए सभी प्रयास करना है।

हम मानते हैं कि ग्रामीण भारत में शिक्षा पहुंचाने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों की सराहना की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने देश में 60 नए नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है। इस समय देश में 594 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जिनमें 2.35 लाख विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं। सरकार ने इस वर्ष देश में 62 नए नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। सरकार सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने को प्रतिबद्ध है और यह उसी दिशा में उठाया गया कदम है।

मौजूदा प्राथमिक शिक्षा में आप किस तरह की खामियां देख रहे हैं ?

मेरी नजर में तो बहुत से स्कूल केवल मिड-डे मील वाले विद्यालय बनकर रह गए हैं क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून पारित होने के बाद बच्चे कुछ खास कक्षा तक फेल होते ही नहीं है। ये स्कूल केवल आने, खाने और जाने तक सीमित रह गए हैं। हमने इसे चुनौती के रूप में लिया है और अब सभी कक्षाओं के लिए परिणामों पर अधिक बल देने का निर्णय किया है। हमारे सामने एक ऐसा विधेयक भी विचाराधीन है जो कक्षा पांच से कक्षा आठ के उन छात्रों को फेल करने की अनुमति प्रदान करेगा जो शिक्षा के न्यूनतम स्तर तक नहीं पहुंचते क्योंकि राज्य फेल नहीं करने की नीति में संशोधन की मांग कर रहे हैं। यह एक गंभीर समस्या है कि कक्षा छह का छात्र कक्षा दो का

पाठ पढ़ने में या कक्षा सात का छात्र कक्षा तीन का गणित का सवाल हल करने में विफल रहे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह फैसला किया गया है कि मानक में सुधार के लिए कदम उठाने वाले राज्यों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत और पैसा दिया जाएगा।

अकसर देखा जाता है कि गांव देहात में या शहरी क्षेत्रों में बहुत से बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। उनके सामने आर्थिक, सामाजिक या कई बार परिवेश की दिक्कतें होती हैं। उनके बारे में क्या कोई खास कदम उठाने के बारे में सोचा जा रहा है। ? हां हमने इस दिश में भी सोचा है। सरकार स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों को मुक्त विद्यालय व्यवस्था के जरिए कम-से-कम माध्यमिक शिक्षा पूरी करने को लेकर प्रेरित करने का प्रयास कर रही है और इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने की योजना पर विचार चल रहा है। हर साल पांच लाख छात्र इस व्यवस्था के जरिए अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं अब लक्ष्य दस लाख का होना चाहिए। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) इस दिशा में विशेष प्रयास कर रहा है। हमारी कोशिश ऐसे लोगों को विश्वास में लेने के लिए अभियान चलाने की है जिन्होंने आठवीं या नौवीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली थी लेकिन दसवीं पास नहीं कर सके थे। हम उन्हें नेशनल स्कूलिंग के जरिए ऐसा करने को कहेंगे।

इन दिनों देश भर में कई जगहो पर सीबीएसई से संबंद्ध स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने और उनके गैर जिम्मेदाराना रुख पर काफी बवाल हो रहा है। क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाने के बारे में सोच रही है ?

मेरी निगाह में तो सीबीएसई स्कूलों के लिए एक नियामक तंत्र (रेगुलेटर मकेनिज्म) की जरूरत है। जहां तक शिक्षा की गुणवत्ता और अनुचित फीस लेने का सवाल है तो ऐसा नहीं है कि ये बातें हमारी जानकारी में नहीं हैं। मैं इस पर रोक लगाऊंगा और इनकी जवाबदेही तय करूंगा। इन स्कूलों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही उचित फीस लेगी होगी। यही नहीं, हमारी कोशिश बच्चों की शिक्षा में स्कूल के साथ अभिभावक की भूमिका को भी तय करने की है। अगले सत्र से हर स्कूल की कक्षा के सामने यह लिखा होगा कि इस कक्षा के बच्चे को क्या आना चाहिए।

जवाबदेही के लिए शिक्षक को लिखकर देना होगा कि अमुक बच्चे को क्या-क्या आ रहा है। अभिभावक लिखित रूप से इसे पुष्ट करेंगे। सब कुछ स्कूल व शिक्षक के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अभिभावक भी जवाबदेह बनें। मसलन वह रोज बच्चे से पूछें कि शिक्षक आए थे कि नहीं। आए थे तो क्या पढ़ाया। बच्चे को घर पर तीन घंटे पढ़ने के लिए प्रेरित करें। हर बच्चा खुद में खास है। शिक्षक और अभिभावक का फर्ज है कि वह इसे जानें और उजागर करें। सरकार ने तय कर दिया है कि कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को क्या आना चाहिए, इसके लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों को पत्र लिख चुका हूं। शीघ्र ही बैठक भी करूंगा।

शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत
शिक्षा में गुणात्मक सुधार की जरूरत
प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक बदलाव
ब्रेन ड्रेन रोकना सरकार की प्राथमिकता
शिक्षा में स्वायत्तता पर जोर
यूजीसी में सुधार प्रस्तावित
बच्चों के ज्ञान का स्तर परिभाषित
पढ़ाई छोड़ने वालों के लिए मुक्त विद्यालय
सीबीएसई के लिए नियमक संस्था की जरूरत

बढ़ते समुद्र, घटते ग्लेशियर, लगभग 100 प्रतिशत ग्लोबल वार्मिंग का कारण इंसानः यूएन जलवायु समिति

जलवायु परिवर्तन पर आई आईपीसीसी की हालिया रिपोर्ट बताती है कि अगर पृथ्वी के जलवायु को जल्द स्थिर कर दिया जाए, तब भी जलवायु परिवर्तन के कारण जो क्षति हो चुकी है, उसे सदियों तक भी ठीक नहीं किया जा सकेगा। आईपीसीसी इस बात की पुष्टि करता है कि 1950 के बाद से अधिकांश भूमि क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी, हीटवेव और भारी बारिश भी लगातार और तीव्र हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे 'मानवता के लिए कोड रेड' क़रार दिया है।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की तरफ से बीते सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी की जलवायु इतनी गर्म होती जा रही है कि एक दशक में तापमान संभवतः उस सीमा के पार पहुंच जाएगा, जिसे दुनिया भर के नेता रोकने का आह्वान करते रहे हैं। यूएन ने इसे 'मानवता के लिए कोड रेड" करार दिया है।

अमेरिका के वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र की वरिष्ठ जलवायु वैज्ञानिक और इस रिपोर्ट की सह-लेखक लिंडा मर्न्स ने कहा, 'इस बात की गारंटी है कि चीजें और बिगड़ने जा रही हैं। मैं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं देख पा रही जो सुरक्षित है। कहीं भागने की जगह नहीं है, कहीं छिपने की गुंजाइश नहीं है।"

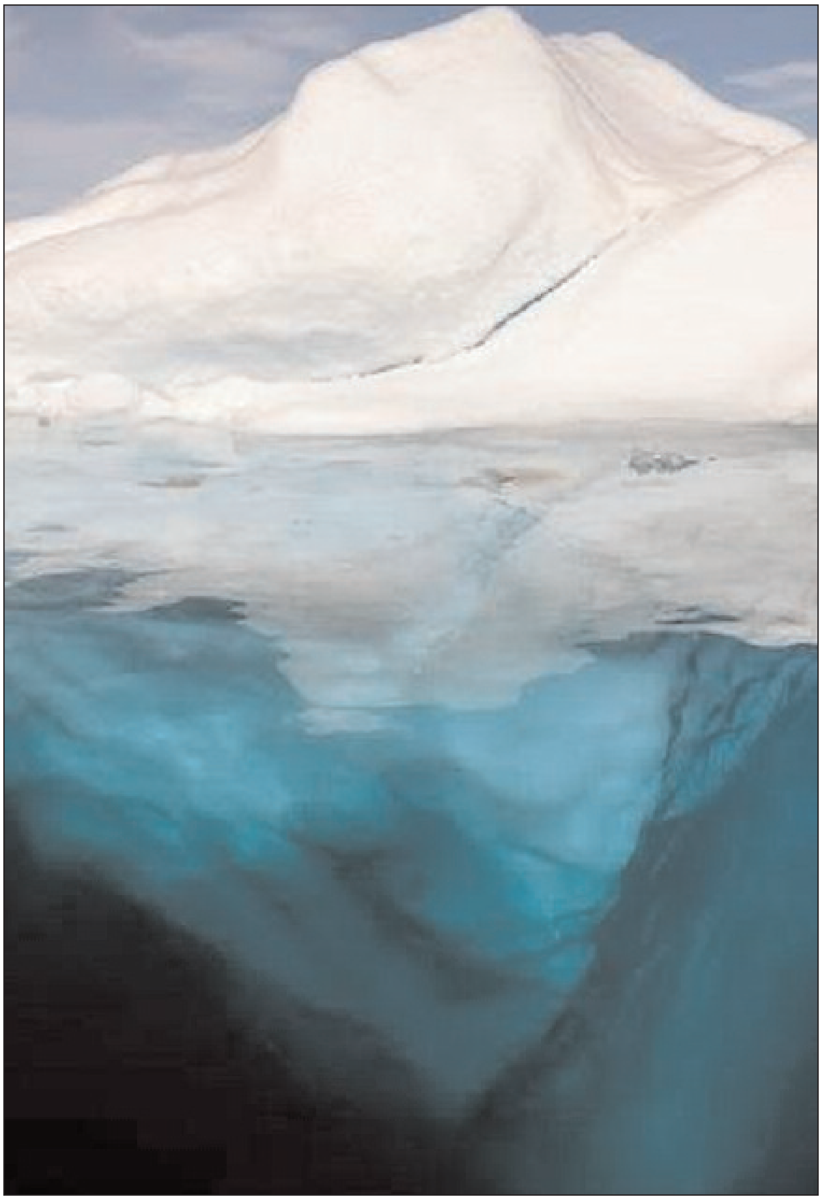

वैज्ञानिक हालांकि जलवायु तबाही की आशंका को लेकर थोड़ी ढील देते हैं।

जलवायु परिवर्तन पर अधिकार प्राप्त अंतर सरकारी समिति (आईपीसीसी) की रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन को पूर्णतः मानव निर्मित करार देती है। यह रिपोर्ट पिछली बार 2013 में जारी रिपोर्ट की तुलना में 21वीं सदी के लिए ज्यादा सटीक और गर्मी की भविष्यवाणी करती है। आईपीसीसी की अब तक की सबसे गंभीर रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व-औद्योगिक समय (1850-1900) के बाद से पृथ्वी का तापमान 1.09 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और कई बदलाव जैसे कि समुद्र के स्तर में वृद्धि और ग्लेशियर का पिघलना अब लगभग अपरिवर्तनीय है।

रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन से बचना अब संभव नहीं है। जलवायु परिवर्तन अब पृथ्वी पर हर महाद्वीप, क्षेत्र और महासागर और मौसम के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है।

साल 1988 में पैनल के गठन के बाद से लंबे समय से प्रतीक्षित रिपोर्ट अपनी तरह का छठा आकलन है। यह नवंबर में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन से पहले दुनिया के नेताओं को जलवायु परिवर्तन के बारे में सबसे सामयिक, सटीक जानकारी देगा।

आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्र और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का शीर्ष जलवायु विज्ञान निकाय है। यह पृथ्वी की जलवायु की स्थिति और मानव गतिविधियां इसे कैसे प्रभावित करती हैं, पर राय देने वाला वैश्विक प्राधिकार है।

आईपीसीसी रिपोर्ट के लेखकों ने दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिकों के काम से मिली जानकारी के आधार पर इस मूल्यांकन को तैयार किया है। यह 3900 पन्नों का दस्तावेज है।

भारत को जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण की

जरूरत

पर्यावरण विशेषज्ञों ने बीते 10 अगस्त को कहा कि भारत को मौसम संबंधी असीम घटनाओं के बढ़ते प्रभावों से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाते हुए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वरना जलवायु परिवर्तन के मजबूत प्रभाव जारी रहेंगे, जिनके बारे में हाल की आईपीसीसी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है।

रिपोर्ट के लेखकों में से एक कृष्ण अच्युत राव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मजबूत प्रभाव तब तक जारी रहेंगे जब तक उत्सर्जन शून्य नहीं हो जाता।

उन्होंने कहा, 'आगामी जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम भारत और बाकी दुनिया के लिए समान हैं। इनमें ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) विशेष रूप से कार्बन-डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को तेजी से कम करना शामिल है। इसे प्राप्त करने के लिए कठोर निर्णय लेने होंगे।"

राव ने कहा, 'यह संदेश भी स्पष्ट है कि हम पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अनुभव कर रहे हैं और जब तक उत्सर्जन शून्य नहीं हो जाता है, तब तक हमारा जोरदार प्रभावों से सामना होता रहेगा, जिसका अर्थ है कि हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम इन परिवर्तनों को कैसे अनुकूलित करते हैं ताकि हमारी आबादी, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बहुत हद तक कम किया जा सके।"

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया) जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा कार्यक्रम के निदेशक टीएस पंवार ने इसी तरह का विचार साझा करते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि से निपटने में देरी से दुनियाभर में जलवायु कार्रवाई के विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं।

उन्होंने कहा, 'भारत जलवायु परिवर्तन के मामले में सबसे संवेदनशील देशों में से एक है और यह बाढ़, चक्रवात, लू, जंगल की आग और सूखे जैसी मौसम संबंधी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि के कारण महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होगा। चूंकि कार्रवाई के लिए समय कम बचा है, लिहाजा भारत को जलवायु कार्रवाई को मुख्यधारा में लाने के लिए सभी क्षेत्रों में अनुकूलन प्रयासों में तेजी लाने और लचीलापन क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है।"

ग्रीनपीस इंडिया के वरिष्ठ जलवायु प्रचारक अविनाश चंचल ने मजबूत और साहसिक कदमों का आह्वान करते हुए कहा कि देश को तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने और भविष्य में जीवाश्म ईंधन में किसी भी निवेश से दूरी बनाते हुए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर दुनिया अब साल 1850 और 1900 के बीच की अवधि की तुलना में 1.09 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। आकलन से पता चलता है कि समुद्र की सतह 1850 के बाद से भूमि की सतह की तुलना में वैश्विक औसत के रूप में लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस कम गर्म हुई है, लेकिन समुद्र के गर्म होने का लगभग दो तिहाई पिछले 50 बरस में हुआ है।

यह स्पष्ट है कि मनुष्य ग्रह को गर्म कर रहे हैं: आईपीसीसी रिपोर्ट

पहली बार आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य वातावरण, भूमि और महासागरों में महसूस की गई वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं।

आईपीसीसी ने पाया कि पृथ्वी की वैश्विक सतह का तापमान 1850-1900 से पिछले दशक के बीच 1.09 डिग्री सेल्सियस बढ़

चुका है। यह साल 2013 में आई पिछली आईपीसीसी रिपोर्ट की तुलना में 0।29 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है।

आईपीसीसी ने यह पाया है कि 1।09 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि में से 1।07 डिग्री सेल्सियस का तापमान मानवीय गतिविधियों से जुड़ीं ग्रीनहाउस गैसों के कारण बढ़ा है। दूसरे शब्दों में, लगभग सभी ग्लोबल वार्मिंग मनुष्यों के कारण हो रहे हैं।

कम से कम पिछले 2,000 वर्षों में किसी भी अन्य 50 वर्ष की अवधि की तुलना में 1970 के बाद से अब तक के 50 वर्ष में वैश्विक सतह का तापमान तेजी से गर्म हुआ है, साथ ही यह वार्मिंग 2,000 मीटर से नीचे समुद्र की गहराई तक पहुंच रही है।

आईपीसीसी का कहना है कि मानवीय गतिविधियों ने वैश्विक वर्षा (बारिश और हिमपात) को भी प्रभावित किया है। 1950 के बाद से कुल वैश्विक वर्षा में वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ क्षेत्र ज्यादा गीले हो गए हैं, जबकि अन्य सूखे हो गए हैं।

अधिकांश भू-क्षेत्रों में भारी वर्षा की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्म वातावरण अधिक नमी धारण करने में सक्षम है- प्रत्येक अतिरिक्त तापमान के लिए लगभग 7 प्रतिशत अधिक- जो गीले मौसम और वर्षा की घटनाओं को बढ़ाता है।

कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च मात्रा तेजी से बढ़ रही है

वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की वर्तमान वैश्विक सांद्रता (कन्सन्ट्रेशन) अधिक है और कम से कम पिछले 20 लाख वर्षों में किसी भी समय की तुलना में तेजी से बढ़ रही है।

औद्योगिक क्रांति (1750) के बाद से जिस गति से वायुमंडलीय CO_2 में वृद्धि हुई है, वह पिछले 8,00,000 वर्षों के दौरान किसी भी समय की तुलना में कम से कम दस गुना तेज है और पिछले पांच करोड़ 60 लाख वर्षों की तुलना में चार से पांच गुना तेज है।लगभग 85 प्रतिशत CO_2 उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन (fossil fuel) के जलने से होता है। शेष 15 प्रतिशत भूमि उपयोग परिवर्तन, जैसे वनों की कटाई और क्षरण से उत्पन्न होते हैं। अन्य ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता भी कुछ बेहतर नहीं है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों, CO_2 के बाद ग्लोबल वार्मिंग में दूसरे और तीसरे सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं, वे भी तेजी से बढ़े हैं। मानव गतिविधियों से मीथेन उत्सर्जन बड़े

पैमाने पर पशुधन और जीवाश्म ईंधन उद्योग से आता है। नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्य रूप से फसलों पर नाइट्रोजन उर्वरक के उपयोग से होता है।

अत्यधिक गर्मी और भारी बारिश भी लगातार वृद्धि

आईपीसीसी इस बात की पुष्टि करता है कि 1950 के बाद से अधिकांश भूमि क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी, हीटवेव और भारी बारिश भी लगातार और तीव्र हो गई है।

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हाल ही में गर्मी की कुछ चरम सीमाओं को देखा गया है, जैसे कि 2012-2013 की ऑस्ट्रेलियाई गर्मी, जो जलवायु पर मानव प्रभाव के बिना एकदम नामुमकिन है।

जटिल चरम घटनाओं में पहली बार मानव प्रभाव का भी पता चला है। उदाहरण के लिए, एक ही समय में होने वाली हीटवेव, सूखा और आग लगने की घटनाएं अब अधिक बार होती हैं। इन मिश्रित घटनाओं को ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप, उत्तरी यूरेशिया, अमेरिका के कुछ हिस्सों और अफ्रीकी उष्णकटिबंधीय जंगलों में देखा गया है।

महासागर: गर्म, ऊंचे और अधिक अम्लीय

महासागर 91 प्रतिशत ऊर्जा को वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि से प्राप्त करते हैं। इसने समुद्र के गर्म होने और अधिक समुद्री हीटवेव को जन्म दिया है, खासकर पिछले 15 वर्षों में।समुद्री गर्मी की वृद्धि समुद्री जीवन की सामूहिक मृत्यु का कारण बनती हैं, जैसे कि कोरल ब्लीचिंग की घटनाओं से। वे शैवाल के बनने और प्रजातियों की संरचना में बदलाव का कारण भी बनते हैं। भले ही दुनिया वार्मिंग को 1.5-2.0 तक सीमित कर दे, जैसा कि पेरिस समझौते के अनुरूप है, सदी के अंत तक समुद्री हीटवेव चार गुना अधिक हो जाएगा।बर्फ की चादरें तथा हिमनद पिघलने और गर्म होने के कारण समुद्र के पानी के फैलने के साथ-साथ, 1901 और 2018 के बीच वैश्विक औसत समुद्र स्तर में 0.2 मीटर की वृद्धि हुई है। लेकिन, महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्र का स्तर बढ़ने की गति भी बढ़ रही है। यह 1901-1971 के दौरान 1.3 मिलीमीटर प्रति वर्ष रही थी। वहीं 1971-2006 के दौरान प्रति वर्ष 1.9 मिमी और 2006-2018 के दौरान 3.7 मिमी प्रति वर्ष रही है। CO_2 बढ़ने के कारण महासागर का अम्लीकरण सभी महासागरों में हुआ है और दक्षिणी महासागर और उत्तरी अटलांटिक में 2,000 मीटर से अधिक गहराई तक पहुंच रहा है।

कुई बदलाव अपरिवर्तनीय हो चुके हैं

आईपीसीसी का कहना है कि अगर पृथ्वी की जलवायु को जल्द स्थिर कर दिया जाए, तब भी जलवायु परिवर्तन के कारण जो क्षति हो चुकी है, उसे सदियों या सहस्राब्दियों तक भी ठीक नहीं किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए इस सदी में 2 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग से 2,000 वर्षों में औसत वैश्विक समुद्र स्तर में दो से छह मीटर की वृद्धि होगी, और अधिक उत्सर्जन होने पर और भी ज्यादा।विश्व स्तर पर ग्लेशियर साल 1950 से लगातार घट रहे हैं और वैश्विक तापमान के स्थिर होने के बाद दशकों तक इनके पिघलते रहने का अनुमान है। इसी तरह CO_2 उत्सर्जन बंद होने के बाद भी गहरे समुद्र का अम्लीकरण हजारों वर्षों तक बना रहेगा।मालूम हो कि हर सात साल या इसके आसपास, आईपीसीसी जलवायु की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी करता है। यह जलवायु परिवर्तन के विज्ञान, इसके प्रभाव और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर सबसे अपडेटेड, सहकर्मी-समीक्षित शोध का सारांश होता है।

क्वालीफाई कराने के नए ठेकेदार

दो- दो लाख में इंजीनियर, डॉक्टर, तीन-चार लाख खर्चो तो आईएएस में निकालने की गारंटी। लॉ कराना है, सीए बनाना है तो थोड़े कम पैसे लगेंगे। ये वो बोली है जो विज्ञापनों के जरिए आज देश के बहुतेरे शहरों के घरों तक पहुंच रही है। कुकुरमुत्तों की तरह जगह जगह खुल गए इन कोचिंग संस्थानों ने जैसे देश की हर प्रतियोगी परीक्षा में क्वालीफाई कराने का ठेका ले रखा है। निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों की मिलीभगत से एक उपभोक्ता के रूप में छात्रों का जम कर शोषण किया जा रहा है। उसके साथ हो रहे इस छल और शोषण के भागीदार तंत्र के हर पहलू की पड़ताल कर रही है ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका के ये कवर स्टोरी...

शिक्षा का मौजूदा स्वरूप

अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने वर्ष 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशंस" में लिखा था कि राज्य को तीन कार्यों को हमेशा अपने हाथ में रखना चाहिए क्योंकि उन्हें निजी हाथों में देकर मुनाफे की दृष्टि से उनके संचालन के कारण देश का भला नहीं, बल्कि भारी नुकसान होगा।

इनमें से पहला है, देश की बाहरी हमलों से पुख्ता सुरक्षा। दूसरा है, देश की कानून व्यवस्था को कायम रखना और इसके लिए आवश्यक पुलिस, न्यायालय आदि की व्यवस्था करना। राज्य की तीसरी जिम्मेदारी है, ऐसे सार्वजनिक कार्यों और सार्वजनिक संस्थानों का पोषण करना जो किसी भी व्यक्ति की क्षमता के परे है। उदाहरण के लिए अच्छी सड़कों, पुलों, नहरों, बंदरगाहों का निर्माण आदि जिनके बिना देश का व्यापार नहीं चल सकता। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं को नागरिकों को प्रदान करना और शिक्षा की व्यवस्था करना क्योंकि इन्हें मुनाफे की दृष्टि से संचालित करने के लिए अगर छोड़ा गया तो इससे देश और समाज का भारी नुकसान होगा। और ये व्यवस्थाएं पैसे वालों की गुलाम बन कर रह जाएंगी।

भारत में शिक्षा की कहानी कुछ - कुछ ऐसी है जो इससे मेल खाती है। कहने को तो यहां सरकारी स्कूल हैं, विश्वविद्यालय हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, प्रोफेशनल कॉलेज हैं। सब कुछ है लेकिन उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। संसाधनों की कमी, शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव, वैज्ञानिक सोच और दिशा का अभाव, रोजगारपरक शिक्षा का अभाव, बहुत से ऐसे कारक हैं जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में साफतौर पर देखे जा सकते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार, दक्षिण एशिया के देशों के आधे और अफ्रीका के एक तिहाई बच्चे जिन्होंने चार साल स्कूलों में बिताए हैं वे ठीक ढंग से कुछ पढ़ भी नहीं पाते हैं। भारत में छह साल से 14 साल के बच्चों में से साठ प्रतिशत बच्चे न पढ़ पाते हैं और न लिख पाते हैं। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की कड़वी हकीकत है।

सरकार हर साल शिक्षा पर काफी पैसे खर्च कर रही है। सरकारी स्कूल चल रहे हैं, कौशल विकास की एक मुहिम से छिड़ी हुई है। नए जमाने के साथ शिक्षा में भी तमाम तरह के नए प्रयोगों का दौर चल पड़ा है। प्रतिस्पर्धा इस दौर की सबसे बड़ी खूबी भी है और कमी भी। खूबी इस दृष्टि से विद्यार्थियों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ होती है। वे खूब मेहनत करते हैं, ज्यादा काबिल बनते हैं और अपने स्तर को सुधारने की कोशिश करते हैं। कमी इस बात से समझी जा सकती है कि यही प्रतिस्पर्धा विद्यार्थियों में निराशा, हीन भावना, गलाकाट प्रतियोगिता और सफलता के लिए गलत रास्तों को अपनाने की तरफ भी ले जाती है।

मां-बाप भी वक्त की नजाकत को भांपते हुए अपने बच्चे को जमाने में किसी लिहाज से पीछे नहीं छोड़ना चाहते। वे अपना पेट काट कर भी बच्चे की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करना चाहते। दरअसल इसी सोच और प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाते हैं समानांतर शिक्षा व्यवस्था चलाने वाले कोचिंग संस्थान। इन्हें शिक्षा माफिया का नाम देना भी गलत न होगा। शिक्षा व्यवस्था के पेशेवर होने के साथ तेजी से इस गोरखधंधे का मकड़जाल पांव पसारता जा रहा है। कोई कहता है आईएएस बना देंगे, तो कोई इंजीनियर – डॉक्टर बनाने का दावा करता है। कोई होटल प्रबंधन का कोर्स करा रहा है तो कोई वकील बनाने का दावा कर रहा है। सबकी अपनी अपनी दुकानें है और छात्र और अभिभावक ग्राहक। पैसे दो, गारंटी लो।

एक आंकलन के मुताबिक भारत में कोचिंग उद्योग लगभग पिछले वर्ष करीब 60 अरब डॉलर का था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये आंकड़ा अगले कुछ सालो में तेजी से बढ़कर 500 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। एसोचेम ने एक सर्वे किया जिसमें पाया गया कि मेट्रोपोलिटन शहरों में प्राइमरी स्कूल के 87 प्रतिशत और हाईस्कूल के 95 प्रतिशत बच्चे कोचिंग ले रहे हैं। यह हालात तब हैं, जब इस स्तर पर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती। इन बड़े मेट्रो शहरों में भी स्कूली स्तर पर कोचिंग संस्थानों की सहायता का उभरता ट्रेंड बेहद खतरनाक संकेत देता है। एसोचेम के मुताबिक भारत में 35 फीसदी की दर से कोचिंग का धंधा बढ़ रहा है और देश में मध्यम वर्गीय लोग अपनी आय का एक तिहाई हिस्सा कोचिंग में खर्च कर रहे है ताकि उनके बच्चे जटिल और कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो सकें।

राजस्थान का कोटा शहर निजी कोचिंग का सबसे बड़ा केंद्र है जहां करियर पॉइंट, बंसल, एलन जैसी तमाम संस्थाएं आईआईटी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं इसके अतरिक्त अन्य बड़े शहर भी इससे पीछे नहीं हैं। दिल्ली में आईएएस के लिए वाजीराव, चाणक्य, एएलएस जैसे तमाम संस्थान हैं, हैदराबाद में श्री चैतन्य नारायण, देहरादून में प्रयास आईएएस जैसे बड़े संस्थान विद्यार्थियों को कोचिंग उपलब्ध करा रहे हैं।

हमारे देश में कोचिंग का व्यवसाय इतना अधिक विकसित हो चुका है कि यहां विदेशी निवेश तक होने लगे हैं गेट, मेट, कैट, टोफ्फेल, एलसैट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कुछ संस्थानों में कैप्लेन जैसी कुछ विदेशी कंपनियां तक निवेश कर रही हैं।

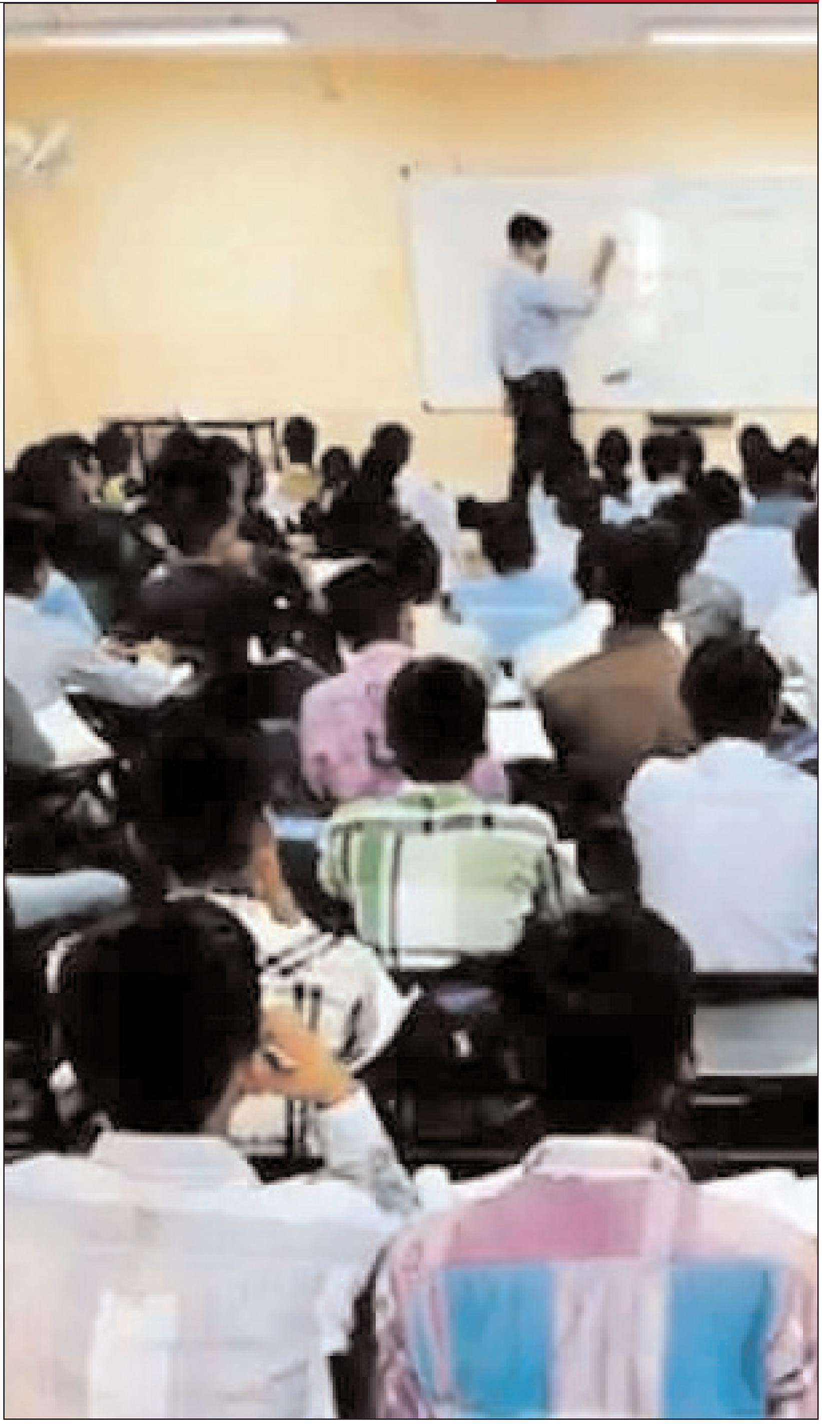

सवाल उठता है आखिर क्यों इतनी तेजी से फैल रहा हैं इन कोचिंग संस्थानों का कारोबार ? कारण तो ढेरों हैं लेकिन कुछ खास कारणों को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है –

स्कूल – कॉलेजों में ढंग से पढ़ाई न होना

भारत में शिक्षा के लिए अधिकतर बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। इन स्कूलों का हाल बेहद खराब है। वहां योग्य शिक्षकों से लेकर जरूरी संसाधनों तक का अभाव है। कहना न होगा कि शहर हो या गांव शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अधिकतर राज्यों में स्कूलों की अपनी इमारतें नहीं हैं। बच्चे पेड़ के नीचे बैठने को मजबूर होते हैं। बैठने के लिए न बेंच हैं और न लिखने के लिए डेस्क। परीक्षा सिर

पर होती है और विषय का कोर्स ही पूरा नहीं हो पाता। आए दिन हड़ताल और छुट्टियों से हाल और बेहाल रहता है। छात्र नकल करके पास होने में भरोसा रखते हैं। स्कूलों का नियंत्रण भी माफिया चाइप लोगों के हाथ में ज्यादा रहता है इसलिए आमतौर पर छात्र हो या अभिबावक सब खामोश रहने में ही भलाई समझते हैं। लेकिन सवाल उठता है जब इस शिक्षा से काम बनना नहीं है तो क्या विकल्प हो सकता है। इसी जगह पर कोचिंग के लिए जमीन तैयार होती है। स्कूल की पढ़ाई से निराश छात्र के पास इन कोचिंग संस्थानों का दामन कोचिंग संस्थानों का रुख करते हैं। कोचिंग संस्थान ये बात बखूबी जानते हैं और वे इसी का फायदा उठाते हैं। इसके एवज में वे आपसे मोटी फीस ऐंठते हैं और आप खुशी खुशी उन्हें देते हैं।

पेशेवर शिक्षा का चलन

पहले शिक्षा का मकसद ज्ञान था। वो ज्ञान जो जीवन मे योग्यता की बुनियाद बनता था। वक्त के साथ शिक्षा का स्वरूप और मकसद दोनों बदलता गया। आज शिक्षा पूरी तरह से व्यावसाय़िक रूप ले चुकी है। पेशेवर शिक्षा का

की भावना

आज कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। जो जीता वही सिकंदर का पाठ पढ़ने वाले बच्चों के लिए सफलता ही सब कुछ है। वे इस सफलता के लिए कुछ भी कर गुजरने से बाज नहीं आते। स्वस्थ प्रतियोगिता की जगह अब गला काट प्रतियोगिता ने ले ली है। उन्हें अगर आईआईटी में जाना है तो वे उसके लिए जीजान लगा देना चाहते हैं और उसके लिए सबसे अच्छी सुविधाओं के साथ कोचिंग लेना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में ऐसी

छामने के अलावा कोई और चारा नहीं होता।

कमाई का धंधा बन जाना

अब शिक्षा सिर्फ शिक्षा नहीं है। शिक्षा कमाई का जरिया भी है। इन कोचिंग संस्थानों में शिक्षा का कारोबार होता है। यहां आप जाते ही तभी हैं जब आपके सामने कोई की मकसद होता है। बच्चे को इंजीनियर बनाना है, आईआईटी में निकालना है, आईएएस बनाना है, बैंक की नौकरी करानी है। और जाने क्या क्या बनाना है। आपके हिसाब से स्कूल कॉलेज की शिक्षा आपकी इस महत्वाकांक्षा के हिसाब से बच्चे को पढ़ा पाने में नाकामयाब है तभी आप इन चलन बढ़ता जा रहा है और उतनी ही तेजी से उस शिक्षा के लिए कोचिंग संस्थानों की तादाद बढ़ रही है। आज आपको लॉ में प्रवेश के लिए अलग कोचिंग संस्तान मिलेंगे तो होटल प्रबंधन के लिए अलग, आईआईटी, मेडिकल, सीए सभी के लिए अलग अलग कोचिंग संस्थान उपलब्ध हैं। स्कूल - कॉलेज की पढ़ाई छोड़ कर बच्चे इन कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करने जाते हैं। उन्हें स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई पर उतना भरोसा नहीं रहा जितना इन कोचिंग संस्थानों पर। वाकई ये चिंता का विषय है।

प्रतिस्पर्धा या पीछे न रह जाने

सुविधाओं के बारे में सोचना भी गुनाह है। जाहिर सी बात है ऐसे में कोचिंग संस्थाओं का रुख ही इन विद्यार्थियों के लिए चारा बचता है।

अभिभावकों का दबाव

हर मां बाप अपने बच्चे को दुनिया के शिखर पर देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाए, बड़ा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या ऐसा कुछ करे कि उनकी नांक देश समाज में ऊंची हो जाए। ये अभिभावक ये नहीं सोचते कि उनके बच्चे की दिलचस्पी किस विषय को पढ़ने में हैं है वो इंजीनियर बनना भी चाहता है या

नहीं। ये उस पर अपनी इच्छाओं का बोझ लाद देते हैं और उसी हिसाब से उसकी पढ़ाई का बंदोबस्त सुनिश्चित करना चाहते हैं। उनके इसी काम में मददगार बनते हैं ये कोचिंग संस्थान। कोचिंग संस्थान दरअसल अभिभावकों की इसी मनोभावना को जम कर इनकैश करते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ उनके अभिभावकों के सपनों से भी खेलते हैं।

सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएंगे

देश में शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर शिक्षा तक बदलाव की आवश्कता महसूस की जा रही है। सरकार ने नई शिक्षा नीति की पूरी तैयारी कर ली है। इसे लागू कैसे किया जाएगा सरकार में इन दिनों इस पर मंथन चल रहा है। अगले 2-3 महीनों में देश के सामने मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति होगी। नई शिक्षा नीति से देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति न सिर्फ प्राइवेट स्कूलों जैसी होगी बल्कि देश भर में लोग सरकारी स्कूलों में दाखिले को पहली प्राथमिकता देंगे।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस

नई शिक्षा नीति में दूसरी बड़ी चिंता शिक्षकों की गुणवत्ता को लेकर हैं। माना जा रहा है कि हमारे देश में शिक्षक को न सिर्फ पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए बल्कि उसकी भूमिका एक प्रेरक के रूप में कहीं ज्यादा होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके। उसके सामने उसका शिक्षक ही उसके सवालों का जवाब हो। सबसे बड़ी कोशिश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वयवस्था के विकास की है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। कोशिश है कि देश के बेस्ट ब्रेन का पलायन रोकने के लिए विश्व स्तरीय शोध की सुविधाएं देश में मुहय्या कराई जाएं। केन्द्र सरकार ने देश के सभी आईआईएम को पूरी स्वायत्तता देने के साथ शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार का अगाज किया है। सरकार अब यूजीसी में सुधार प्रक्रिया शुरू कर रही है। भारत ने ओपन लर्निंग की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अगले कुछ दिनों में उत्कृष्ट शिक्षा के लिए डिजिटल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। यह डिजिटल सॉल्यूशन 'सबको शिक्षा' और 'अच्छी शिक्षा' के लिए बेहद अहम होगा।

संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल

नई शिक्षा नीति में एक और चिंता संसाधानों को लेकर है। वैसे सरकार का जोर उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर ज्यादा है।

महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान

महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की सोच है कि महिला को शिक्षित करने से ही बड़े बदलाव की बुनियाद रखी जा सकती है।

प्राथमिक शिक्षा की मजबूती

सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एलान किया गया है। सरकार के इस एलान से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, प्रवेश परीक्षाएं कराने की एजेंसी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए स्कूलों के लिए एक साथ प्रवेश परीक्षाएं होंगी। एंट्री और एक्जिट परीक्षाएं एक जगह होंगी। लेकिन, बोर्ड परीक्षाएं पहले जैसी ही होंगी। इस तरह की एजेंसी दुनिया में कई

जगह हैं। सरकार की ओर से छात्रों के जीवन में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है और सरकार प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारेगी।

दरअसल ये व्यवस्था सीखने के स्तर को परिभाषित करती है जिसे किसी छात्र से किसी खास कक्षा में अपेक्षा की जाती है। अकादमिक सत्र 2017-18 से पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के छात्रों के सीखने के स्तर से जुड़े विशेष मानकों को नियमों में शामिल किया जाएगा और उसे लागू किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अस्तित्व में है और उसमें लर्निंग आउटकम का जिक्र है लेकिन उसे परिभाषित नहीं किया गया है।

शिक्षा बीच में न छूटे

नई शिक्षा नीति में इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चे शिक्षा को बीच में न छोड़ें। पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरु किए गए सर्व शिक्षा अभियान के परिणाम स्वरुप पिछले कई वर्षों में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान का मकसद सर्वसुलभ नामांकन और लड़कियों सहित सभी बच्चों को स्कूल में लाए जाने के लिए सभी प्रयास करना है।

संक्षेप में कहा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बदलाव की दिशा में काम किया जा रहा है जिससे शिक्षा न सिर्फ ज्ञान का माध्यम बन सके बल्कि उससे रोजगार, उद्यमशीलता और आत्म निर्भरता की सोच को भी विकसित कर सके।

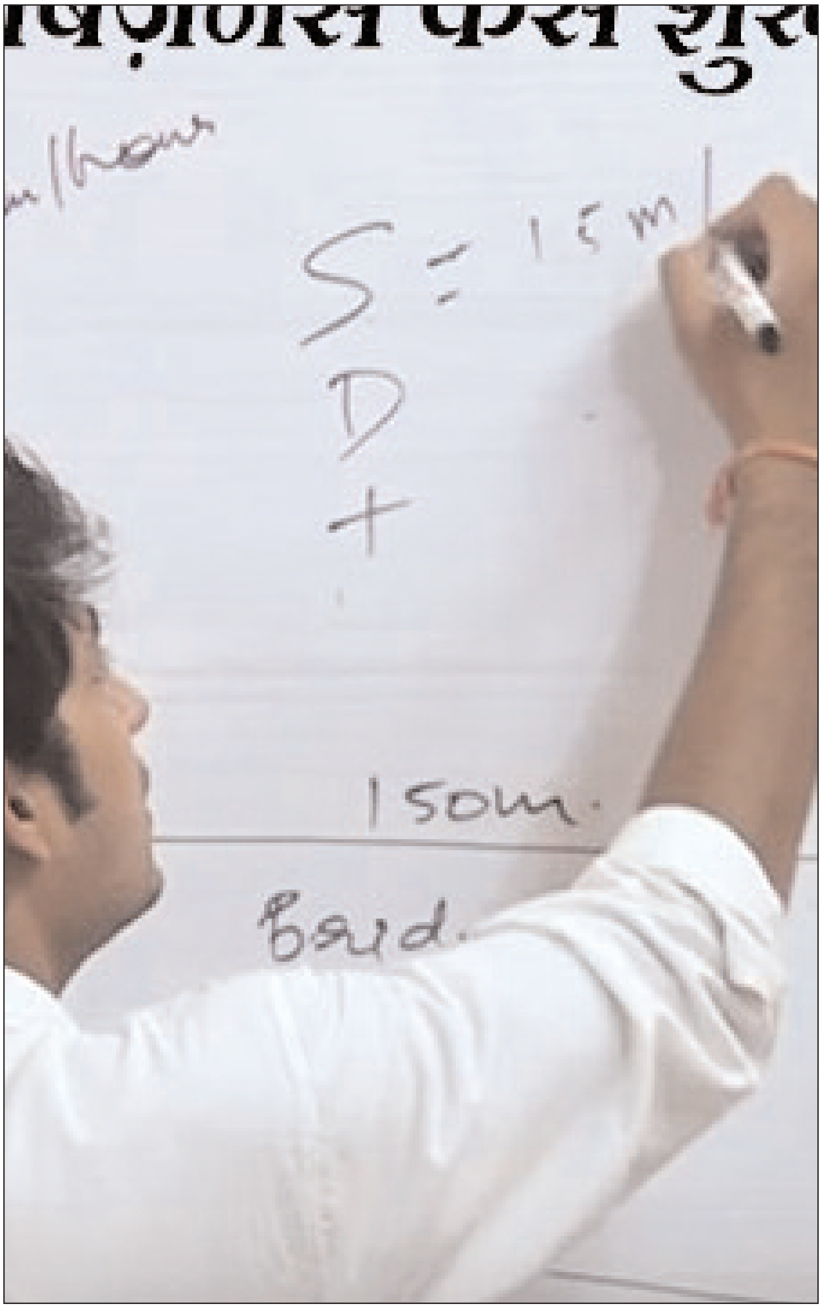

समझिए, निजी स्कूलों और कोचिंग के दुष्चक्र को

सरकारी स्कूलों - कॉलेजों में लचर शिक्षा व्यवस्था की मौजूदगी के पीछे भी असली खेल खेलने वाले यही निजी स्कूल और कोचिंग संस्थान हैं। एक समय था जब इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ी लिखी देश की एक से एक हस्तियां निकली। लेकिन समय के साथ जब शिक्षा व्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी तो उन्हें अपने शिक्षा के कारोबार को फैलाने के लिए विद्यार्थियों का बाजार भी चाहिए था जो उस समय तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा ले रहा था। अब उस बाजार के लिए जरूरी था सरकारी स्कूलो- कॉलेजों की शिक्षा को चौपट किया जाए। तभी तो वहां पढ़ने वाला विद्यार्थी इन निजी क़लेजों की तरफ उन्मुख होता। वही किया गया। सरकारी शिक्षा संस्थाएं बद से बदतर होती गईं और निजी शिक्षा संस्थाएं फलती फूलती गईं। दरअसल इस खेल में कहीं न कहीं सरकारी तंत्र का भी हाथ था। निजी कॉलेज खोलने वाले भी तो यही राजनेता, अफसर और पूंजीपति थे। उनके बच्चे यहीं पढ़ते थे। अगर सरकारी शिक्षण संस्थाएं कमजोर न पड़ती तो या की जातीं तो असर इन निजी कॉलेजों के बाजार पर ही पड़ना था। इसलिए सरकारी शिक्षण संस्थाओं को कमजोर करने के पीछे भी इन निजी शिक्षण संस्थाओं की साजिश ही काम कर रही थी।

सरकारी शिक्षण संस्थाओं को कमजोर करने के बाद भी शिक्षा के कारोबार के पेट नहीं भरा। निजी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी नौकरियों के लिए कोचिंग सेंटर और बहुत सी वे संस्थाएं सामने आईं जो निजी कॉलेजों की संस्तुतियों पर ही पल बढ़ रही थीं।

कोचिंग सेंटरों में पढ़ाने वाले ज्यादातर टीचर आपको वे ही मिलेंगे जो निजी स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ाते हैं। वे खुद अपने विद्यार्थियों को कोचिंग लेने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वहां उनसे और पैसा वसूला जा सके। डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना दिखाने वाले इन कोचिंग सेंटरों को पता है कि अपने बच्चे के

भविष्य के लिए मां बाप अपना पेट काट कर भी पैसे देंगे। कोचिंग सेंटर उन्ही भावनाओं का फायदा उठाते हैं।

इस दुष्चक्र का एक पहलू और भी है। कोचिंग सेंटरों और निजी शिक्षण संस्थाओं के रूप में पनप रहे इन शिक्षा माफिया के फलने फूलने के पीछे देश में तेजी से फैले नव धनाड्य वर्ग की जिम्मेदारी भी कम नहीं। इस वर्ग के पास पैसे तो थे लेकिन सोच नहीं थी। इनकी नजर में पैसे से हर चीज संभव है। उनकी सोच है कि पैसा फेंको और बच्चे को डिग्री दिला दो। इस दुष्चक्र में सबसे ज्यादा बच्चे इसी वर्ग के फंसते हैं।

आंकड़ों को देखिए तो खुद ब खुद बहुत सी बातें साफ हो जाएंगी। आज गांवों के बीस प्रतिशत से अधिक बच्चे निजी स्कूलों में जा रहे हैं। यह प्रतिशत लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज से बीस वर्ष पूर्व मात्र 10 प्रतिशत बच्चे ही निजी स्कूलों में जाते थे। एक सर्वेक्षण के अनुसार, 2006 में मात्र 19 प्रतिशत कुल बच्चे निजी स्कूलों में जाते थे मगर 2013 में यह प्रतिशत बढकर 29 प्रतिशत हो गया। कहते हैं कि भारत जैसे देश में अभिभावकों का झुकाव निजी स्कूलों की ओर इसलिए बढ़ा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और अनुशासन का काफी अभाव है। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जिंदगी में कुछ करें और यह तभी संभव है जब उनकी पढ़ाई-लिखाई ठीक-ठाक हो। उनका ख्याल है कि निजी शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन और पढ़ाई दोनों पर जोर दिया जाता है भले ही फीस और अन्य विभिन्न मुद्दों पर भारी रकम वसूली जाती है।

निगरानी व नियंत्रण जरूरी

कोचिंग संस्थानों पर निगरानी के लिए सरकार को एक निगरानी और विनियमन प्राधिकरण गठित करना चाहिए और कोचिंग संस्थान में क्लास स्ट्रेंथ, फीस निर्धारण, अध्यापकों की योग्यता जैसे कुछ मानक आवश्यक रूप से बनाए जाने चाहिए। प्रतिवर्ष आईएएस की परीक्षा में साढ़े नौ लाख फार्म भरे जाते हैं, जबकि केवल 1100 के आस पास वेकेंसी निकलती है बड़े स्तर पर कोचिंग उपलब्ध हैं, इसी तरह आईआईटी परीक्षा के लिए कुल सीट लगभग नौ हजार होती है लेकिन लगभग 14 लाख बच्चे तैयारी करते हैं इसमें तो ज्यादा भीड़ बढ़ाने का श्रेय कोचिंग संस्थानों को भी जाता है।

इन स्कूलों का खर्च उठाना आपके बस में है ?

हर मां-बाप का सपना होता है कि उसका बेटा-बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े। जहां से वह अच्छी शिक्षा और संस्कार पा सकें और अपने जीवन को संवार सकें। आजकल पढाई में इतनी प्रतिस्पर्धा हो गई है कि यह तय करना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन सा स्कूल सबसे अच्छा है। इतना ही नहीं हमारे देश में तो कुछ स्कूल इतने महंगे हैं कि आम लोगों के लिए इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना नामुमकिन है। यहां पर हर सुविधा का बखूबी ख्याल रखा जाता है और इसी कारण इन स्कूलों का नाम उच्च स्तर के शिक्षण संस्थानों में लिया जाता है।

सिंधिया स्कूल

ग्वालियर की सिंधिया स्कूल देश का बेस्ट स्कूल है। यहां का सलाना खर्च लगभग 8 लाख रुपए है। इस स्कूल में सलमान खान,नील नितिन मुकेश, अनुराग कश्यप के अलावा और

भी कई सैलीब्रिटीज पढ़ चुके हैं। यहां पर एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। आपको बता दें कि यह स्कूल सिर्फ लड़कों के लिए ही है।

गुड शेफर्ड स्कूल

70 एकड़ पर फैला हुआ ऊटी का यह स्कूल नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। यहां पर एक बच्चे की सलाना फीस लगभग 6 लाख से 11 लाख रुपए है। यहां पर मॉडर्न जमाने की हर एडवांस टैक्नीक मौजूद है।

दून स्कूल

देहरादून का दून स्कूल बहुत पुराना स्कूल है। यहां पर लडको को ही पढ़ाया जाता है। इस स्कूल में 500 के करीब बच्चे पढते हैं। यहां पर एक बच्चे की पढ़ाई का सालाना खर्च लगभग 9 लाख 70 हजार रुपए है। इस बॉर्डिंग स्कूल में 13 से 18 साल की उम्र के लड़के पढ़ सकते हैं।

वुडस्टॉक स्कूल

उत्तराखंड के मसूरी में स्थित वुडस्टॉक नाम का यह प्राइवेट स्कूल करीब 250 एकड़ में फैला हुआ है। यहां की सलाना फीस 8 से 9 लाख के करीब है। यहां पर एंडवांस लेबोरेट्री, फिटनेस सेंटर, लाइब्रेरी की पूरी सुविधा है। बढ़िया पढ़ाई और कड़े नियमो के कारण भी स्कूल बहुत विख्यात है। यहां पर एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है।

मर्सिडीज-बेंज इंटरनेशनल स्कूल

पुणे के मर्सिडीज-बेंज इंटरनेशनल स्कूल का नाम भी देश के महंगे स्कूलों में शामिल है। यहां पर लड़के और लड़कियां (Co-education) दोनों ही पढ़ सकते हैं। यहां पर दूसरे देशों से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इस स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए 6 लाख से 16 लाख तक की भारी र कम खर्च करनी पड़ती है।

एकोल मंडेल वर्ल्ड स्कूल

देश की महानगरी मुंबई का एकोल मंडेल वर्ल्ड स्कूल (Ecole Mondiale World School) महंगे स्कूलों में से एक है। यहां का सलाना खर्च 6 लाख रुपए से लेकर 11 लाख रुपए तक है। इस स्कूल में बेमिसाल आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं।

इतने पापड़ बेलो तो खोलो स्कूल !

राजधानी में नया स्कूल खोलने के लिए आधा दर्जन से अधिक विभागों व एजेंसियों से करीब 14 सर्टिफिकेट या अनुमतियां लेनी पड़ती हैं। किसी भी अनुमति या सर्टिफिकेट के जारी होने की कोई तय समय सीमा नहीं है। अलबत्ता, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी का एक अध्ययन है कि हर अनुमति की अवैध रूप से एक फीस तय है, जिसके अदा करने के बाद ही वह सर्टिफिकेट मिल पाता है। इस अध्ययन के मुताबिक राजधानी में कक्षा 5 तक का स्कूल खोलने के लिए करीब 20 लाख रुपए की जरूरत होती है, यदि स्कूल आठवीं तक

आपको क्या ध्यान रखना है?

अभिभावक और छात्र दोनों के लिए ही ये सावधानियां जरूरी हैं-

कोचिंग का चुनाव सोच-समझ कर और जांच - परख कर करें।

अपनी जरूरत को ध्यान में रख कर कोचिंग लें।

कोचिंग में प्रवेश लेते समय उसके पिछले रिकॉर्ड को देखें।

सारी बातें लिखित दस्तावेज के रूप में कोचिंग से मांगे और उन्हें सुरक्षित रखें।

कक्षाओं और स्टडी मटीरियल के बारे में लिखित में जानकारी मांगें। फीस संबंधी सारी रसीदें सुरक्षित रखें।

ध्यान रखें कि आपसे किए गए वादे पूरे जा रहे हैं या नहीं।

आपको बता दें कि आप उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत संरक्षण प्राप्त हैं।

कोई भी वह सेवा जिसके एवज में पैसे दिए गए हों वह उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत है।

अगर आपको सेवा में कोई नजर आती है तो आप संबंधित कोचिंग सेंटर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज करा सकते हैं।

खोलना है तो यह राशि 40-50 लाख रुपए तक पहुंच जाती है और दसवीं तक के लिए यही राशि एक करोड़ रुपए चाहिए। 12वीं तक का स्कूल खोलने के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। इस राशि में स्कूल की जमीन की कीमत शामिल नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि स्कूल खोलने के लिए वास्तव में कितने सर्टिफिकेट व अनुमतियां आवश्यक हैं। यह स्थिति केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में है। अकेले दिल्ली में साढ़े पांच हजार से ज्यादा सरकारी व निजी स्कूल हैं लेकिन इसके बावजूद करीब लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं।

स्कूल खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में निजी बजट स्कूलों की संस्था नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलाएंस (निसा) ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को एक विस्तृत सुझाव भेजा है। निसा का कहना है कि एक तरफ जब देश में गुणवत्तापूर्ण स्कूलों की कमी है, ऐसे में स्कूल खोलने की प्रक्रिया को कम पेचीदा व पारदर्शी बनाए जाने की जरूरत है। यह कहां तक उचित है कि स्कूल खोलने के लिए महज अनुमतियां लेने में ही तीन से पांच साल लग जाएं।

निसा का सुझाव है कि सबसे पहले, सरकार को एक पन्ने की चेकलिस्ट प्रकाशित करनी चाहिए ताकि पता चल सके स्कूल खोलने के लिए कितने सर्टिफिकेट, एनओसी, रजिस्ट्रेशन, मंजूरियां या लाइसेंस लेने जरूरी हैं। सबकी मंजूरी या नामंजूरी की समयसीमा तय हो। पूरी प्रक्रिया सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए हो। रजिस्ट्रेशन, आवेदन, फिर आवेदन की ट्रैकिंग व मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन की जाए। अभी स्कूल खोलने के लिए करीब 15 आवेदन भरने पड़ते हैं, उन्हें खत्म करके एक एकीकृत आवेदन फॉर्म बना दिया जाए। हर विभाग आवेदन मिलने के बाद दो हफ्ते के भीतर उस पर फैसला अवश्य कर दे। वेबसाइट पर पूरी आवेदन प्रक्रिया का डेमो उपलब्ध हो, बार-बार पूछे जाने वाले सवाल व उनके जवाब के साथ-साथ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किए जाएं।

क्या है प्रक्रिया ?

दिल्ली में स्कूल खोलने के लिए सबसे पहले एक सोसाइटी (मुनाफा न कमाने वाली) रजिस्टर करनी पड़ती है। फिर शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्ति प्रमाणपत्र, सीबीएसई से संबद्धता प्रमाणपत्र, जमीन की खरीद का उचित हलफनामा, भवन योजना की एमसीडी या डीडीए से मंजूरी, एमसीडी से भवन का फिटनेस प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, दिल्ली जल बोर्ड से पानी जांच रिपोर्ट, बैंक से नो लोन सर्टिफिकेट, डीडीए से कंपलीशन सर्टिफिकेट, शिक्षा विभाग से मंजूर प्रबंधन स्कीम, जमीन मालिक से जमीन के इस्तेमाल का प्रमाणपत्र (यदि जमीन किराए पर है)। मान्यता प्रमाणपत्र के लिए भी कम से कम 15 दस्तावेज जमा करने होता हैं।

इस पत्रकार की तनख्वाह बढ़ जाती तो शायद दुनिया में मार्क्सवाद ना होता

पत्रकारों को कम वेतन नहीं देना चाहिए। कम वेतन पाने वाला पत्रकार अधिक खतरनाक हो सकता है। कभी ये रोचक निष्कर्ष निकाला था, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने। कार्ल मार्क्स पर उनकी ये एक रोचक टिप्पणी है। ये कथन जॉन एफ कैनेडी के ओवरसीज प्रेस क्लब न्यूयॉर्क में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में, 6 मई 1957 को दिए गए भाषण का एक अंश है। ये भाषण जब वे सीनेटर थे तब उन्होंने दिया था। कार्ल मार्क्स, कभी न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में एक पत्रकार की हैसियत से काम करते थे। लेकिन उन्हें जो पारिश्रमिक मिलता था, वो उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं होता था। मार्क्स, उस अखबार में फॉरेन करेसपोंडेंट थे। उन्होंने बाद में अखबार की नौकरी छोड़ दी और फिर जिस काम में वे जुटे उसने दुनिया बदल कर रख दिया। उनकी सोच और विचारधारा ने लेनिन, स्टालिन, माओ, कास्त्रो और चे जैसे लोगों को जन्म दिया, जिन्होंने दुनिया में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दर्शन और बाद में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से उद्भूत विचारधारा के आधार पर दुनिया में बदलाव और क्रांति की पीठिका रखी।

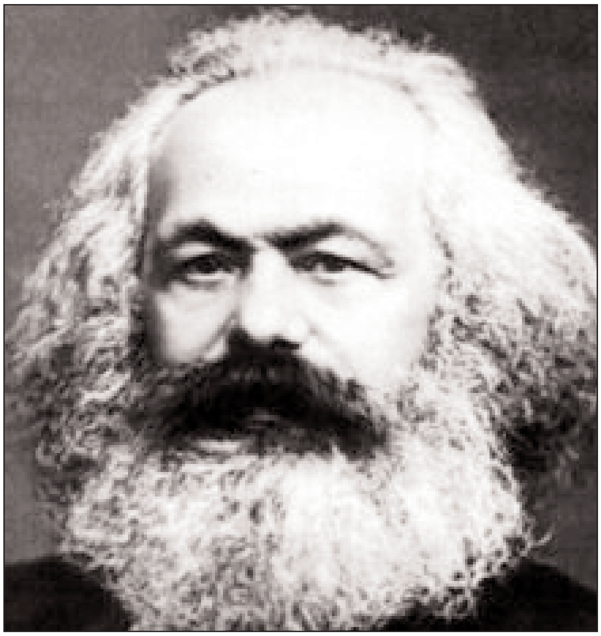

पूरा किस्सा इस प्रकार है। 1851 में न्यूयॉर्क ट्रिब्यून के प्रकाशक और सम्पादक होर्स ग्रीली ने लंदन में काम कर रहे एक फ्रीलांस पत्रकार कार्ल मार्क्स को अपने अखबार में विदेश संवाददाता के रूप में नौकरी पर रखा। मार्क्स लंदन से ही, उस अखबार के लिए विदेशी मामलों पर अपने डिस्पैच भेजते थे। तब लंदन दुनिया के साम्राज्यवाद का नाभिस्थल था और मार्क्स की टिप्पणियों को बेहद रुचि और उद्विग्नता से पढ़ा भी जाता था। मार्क्स उस अखबार के लिए नियमित रूप से कॉलम लिखने लगे। जब कभी मार्क्स किसी अन्य अध्ययन में व्यस्त हो जाते तो, वो कॉलम उनके साथी फ्रेडरिक एंगेल्स लिख दिया करते थे। वैचारिक और दृष्टिकोणीय समानता के कारण, दोनों के लेखन और तार्किकता में कोई बहुत अंतर होता भी नहीं था। इस अखबार में नौकरी के दौरान कार्ल मार्क्स की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और वे निरन्तर अर्थाभाव में रहने लगे। उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए अखबार के मालिक ग्रीली और प्रबंध संपादक चार्ल्स डाना से अनुरोध किया और कम से कम 5 डॉलर की वृद्धि करने की मांग की। लेकिन अखबार ने भी ये कह कर कि उसकी भी आर्थिक स्थिति अमेरिकी गृह युद्ध के कारण अच्छी नहीं है कार्ल मार्क्स की तनख्वाह बढ़ाने से मना कर दिया। इस पर मार्क्स और एंगेल्स ने अखबार पर उन्हें ठगने और अपने शोषण करने की क्षुद्र पूंजीवादी सोच से ग्रस्त होने का आरोप लगाया और उन्होंने ट्रिब्यून की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद वे अपने अध्ययन और दर्शन को समृद्ध करने में एंगेल्स के साथ पूरी तरह से जुट गए। फिर जो हुआ, वो बौद्धिक क्षेत्र में एक ऐसा बदलाव था, जिसने दुनिया को बदल दिया।

इसी प्रकरण पर हल्के फुल्के अंदाज़ में जॉन एफ कैनेडी टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि, यदि एक बार इस पूँजीवादी न्यूयॉर्क ट्रिब्यून अखबार उन (कार्ल मार्क्स) से अधिक दयालुता से पेश आया होता और कार्ल मार्क्स यदि उस अखबार में एक विदेश संवाददाता ही बने रहते तो, दुनिया का इतिहास ही कुछ अलग होता। मैं सभी प्रकाशकों से ये आशा करता हूँ कि वे इससे सबक सीखेंगे और भविष्य में ये ध्यान रखेंगे कि अगली बार अपनी गरीबी से पीड़ित यदि कोई व्यक्ति अपने वेतन में थोड़ी भी वृद्धि की मांग करता है तो उस पर विचार करेंगे।

कैनेडी ने भले ही ये बात हल्के फुल्के अंदाज़ में कही हो, पर इसे एक बेहद तार्किक और गम्भीर कथन के रूप में भी देखा जा सकता है। अभाव में जीता हुआ व्यक्ति यदि उक्त अभाव के कारणों की तह में जाता है और जब वो अपने उचित अधिकारों और अभाव के समाधान के लिए समाज में खड़े होकर मुखर होने लगता है तो ना केवल उसकी परिस्थितियां बदलती हैं बल्कि वो समाज को एक दिशा भी देने की हैसियत में आ जाता है।

कैनेडी एक पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश के सेनेटर थे और बाद में वे उस देश के राष्ट्रपति भी बने। उन्हें अमेरिका के बेहतर राष्ट्रपति के रूप में गिना जाता है। ये भी एक विडंबना है कि उनकी हत्या हुई। वे जिस दौर मे थे वो शीत युद्ध का काल था। अमेरिका और सोवियत संघ की आपसी प्रतिद्वंद्विता में दुनिया दो खेमों में बंटी हुई थी। कैनेडी अपने भाषण में यही रेखांकित करते हैं कि बढ़ता हुआ आर्थिक और सामाजिक शोषण, अभाव और विपन्नता में धकेलती हुई राज्य व्यवस्था क्रांति और बदलाव की भूमिका लिखने लगती है। बस उसे नेतृत्व, दिशा, वैचारिक सोच, परिस्थितियों और अवसर की प्रतीक्षा रहती है।

NRAI school of Mass Communication

M-161/1A, G.L. House, Gautam Nagar,
Behind Oil Bhawan (Behind Nirulas) New Delhi-110049,
website.nraismc.com Ph.09899045628

Press Release

(Admission Alert/Notice Board)

Name of Institute: NRAI School of Mass Communication

Course:

1. **P.G.Deploma in Redio joke and tv news reding (Three Months)**
   Eligibility: Graduation in any stream.
2. **Masters in Mass Communication (Advertisement, Journalism) (Two Years)**
   Eligibility: Graduation in any stream.
3. **Bmc (Bachelors of Mass communication) (3 Years)**
   Eligibility: 10+2

4 . Video Editing, Photography& Filmmaking

How to Apply : Prospectus and Application form can be obtained on payment of Rs. 300 in cash or via a DD drawn in favour of the institute, payable at Delhi. Application form can be downloaded from website www.nraismc.com

Contact:- NRAI School of Mass Communication

M-161/1A, G.L. House, Gautam Nagar,
Behind Oil Bhawan (Behind Nirulas) New Delhi-110049,
website.nraismc.com Ph. 09899045628

TGC ANIMATION & MULTIMEDIA

(For Notice Board / Admission Alert Column)

Institute Name: **TGC ANIMATION & MULTIMEDIA, Delhi**

Name of the Course Duration

1. **B.Sc Animation & Multimedia 3 Years.**
2. **M. Sc Animation & Multimedia 2 Years**
3. **Adv. Diploma in Visual Fx and Animation 2 Yrs**
4. **Adv. Diploma in Graphic Design 1 year**
5. **Adv. Diploma in Game Design 1 year**
6. **Adv. Diploma in Web Development 1 year**
7. **Adv. Diploma in Digital Photography 1 Year**
8. **Adv. Diploma in Music Production 1 year**
9. **Adv. Diploma in Python and Data Science 6 months**
10. **Adv. Certification in UI/UX Design 6 months**
11. **Adv. Certification in Video Editing 6 months**
12. **Adv. Certification in Digital Marketing 3 months**
13. **Adv. Certification in CAD/CAM 3 months**

Eligibility of Courses: 10+2 in any stream

HOW to Apply: Prospectus and Application can be obtained on payment of Rs. 200 in cash or DD drawn in favour of the institute, payable at Delhi. Application form can also be downloaded from the website

Website: - www.tgcindia.com

Address:TGC ANIMATION & MULTIMEDIA
H-85A, South Extension, Part-I, New Delhi-110049
Ph: 9582786406/07